विषय सूची / CONTENTS

निदेशक मंडल	Board of Directors	6
आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड	The IFFDC Ltd.	8
हमारा दृष्टिकोण	Our Approach	12
क्रियान्वित परियोजनाओं का विवरण	Details of Projects under Implementation	14
निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	16
प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन	Farm Forestry & Climate Change	19
जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय स्कन्दन)	Watershed Management (Ecological Resilience)	23
आदिवासी व सीमान्त समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)	Nutritional and Economic Security for Tribal & Marginalized Communities (NEST)	27
समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास	Sustainable Rural Livelihood Development	33
सार्वभौमिक अवधान	Cross cutting interventions	38
सामुदायिक संस्थायें	Community Institutions	40
जेन्डर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण	Mainstreaming Gender and Women Empowerment	42
क्षमता निर्माण	Capacity Building	44
परामर्श कार्यक्रम	Consultancy Programme	46
बीज एवं कृषि-आदानों की आपूर्ति	Seed & Agri-inputs Supply	56
मानव संसाधन प्रबंधन	Human Resource Management	58
प्रचार-प्रसार गतिविधियां	Publicity Activities	58
आभार	Acknowledgements	62
पुरस्कार तथा सम्मान	Award and Recognitions	64
सहयोगी संस्थाएं	Support Institutions	66
शेयरधारियों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report to the Shareholders	68

एक दृष्टि

• पंजीयन	–	अक्टूबर 22, 1993 को बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियिम, 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम 2002) के अंतर्गत
• कार्य क्षेत्र	–	सम्पूर्ण भारतवर्ष
• पोर्टफोलियो	–	प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन, जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय स्कन्दन), आदिवासी एवं सीमांत समुदाय के लिए पोषण और आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट), चिरंतर ग्रामीण आजीविका, सार्वभौमिक अवधान (जेंडर को मुख्यधारा से जोड़ना, सामुदायिक संस्थाओं का विकास, क्षमता निर्माण), बीज उत्पादन, कृषि-आदान आपूर्ति एवं परामर्श सेवाएं
• क्रियान्वयन के अन्तर्गत परियोजनायें	–	राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान से 35 परियोजनाएं
• क्रियान्वित ग्रामीण विकास परियोजनाओं की लागत	–	₹ 220 करोड़ से अधिक
• वार्षिक टर्नओवर	–	₹ 471 करोड़
• सदस्य समितियाँ	–	173
• विकसित समितियाँ	–	225 (वानिकी विकास-147, आजीविका विकास-28, आजीविका विकास स्वायत्त-50)
• प्राथमिक समितियों के सदस्य	–	29,695 (38 प्रतिशत महिला सदस्य)
• गठित स्वयं सहायता समूह एवं सदस्यता	–	1,895 (कुल सदस्य 21,512)
• बंजरभूमि पर वृक्षारोपण	–	28452 हैक्ट.
• कुल विद्यमान वृक्ष	–	130.99 लाख
• बीज उत्पादन एवं विपणन	–	2.27 लाख क्विंटल
• आजीविका उत्थान सुनिश्चितीकरण	–	4.30 लाख से अधिक परिवार
• जलग्रहण विकास अंतर्गत क्षेत्र	–	36,208 हैक्ट. पर कार्यरत
• जल संसाधन विकास	–	192 चेक डैम तथा 931 तालाब
• कुल कर्मचारी (सं.)	–	266 (विभिन्न विषयों जैसे कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, वानिकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रोद्योगिकी, वित्त एवं लेखा आदि से)

पंजीकृत कार्यालय
इफको हाउस,
34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

लेखा परीक्षक
मैसर्स एस. टेकरीवाल एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

AT A GLANCE

- **Registration** – On 22nd October, 1993 under Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (subsequently under MSCS Act, 2002)
- **Area of operation** – The whole Indian Union.
- **Portfolio** – Farm Forestry and Climate Change, Watershed Management (Ecological Resilience), Nutritional and Economic Security for Tribal and Marginalized Communities (NEST), Sustainable Rural Livelihoods, Cross Cutting Interventions (Gender Mainstreaming, Community Institution Development, Capacity Building), Seed Production, Agri-Input Supply and Consultancy Services.
- **Projects under Implementation** – 35 Projects in collaboration with various National & International agencies.
- **Rural Development Projects Implemented** – Worth more than ₹ 220 crore.
- **Annual Turnover** – ₹ 471 crore
- **Member Cooperatives** – 173
- **Cooperatives Developed** – 225 (PFFCS-147, PLDCS-28, PLDACS-50).
- **Members of Primary Cooperatives** – 29,695 (38% Women Members).
- **Self Help Groups Formed & Membership** – 1,895 with total membership of 21,512.
- **Wasteland Afforested** – 28,452 ha.
- **Total Existing Trees** – 130.99 lakh.
- **Seed Production and Marketing** – 2.27 lakh quintals.
- **Ensuring Livelihood Improvement** – More than 4.30 lakh families.
- **Area under Watershed Development** – Working on 36,208 ha.
- **Water Resources Development** – 192 Check Dams and 931 Ponds.
- **Total Employees (Number)** – 266 (from various disciplines viz; Agriculture, Agricultural Engineering, Forestry, Social Sciences, Management, Computer & Information Technology, Finance & Accountancy etc.

REGISTERED OFFICE
IFFCO House,
34 - Nehru Place, New Delhi - 110 019

AUDITORS
M/s. S. Tekriwal & Associates
Chartered Accountants, New Delhi

मिशन

संगठित प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों के चिरन्तर प्रबन्धन द्वारा लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्तर का उत्थान।

विज़न

गरीबों की क्षमताओं में वृद्धि करके उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करना एवं उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति हो ताकि वे अपने मूलाधार संसाधनों की वृद्धि एवं विकास कर, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

उद्देश्य

- पारिस्थितिकीय संतुलन एवं चिरंतर ग्रामीण आजीविका संसाधनों के लिए बंजर भूमि का विकास।
- एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास।
- समुदाय की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए लोगों पर केन्द्रित, जेन्डर, टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों/सहकारी समितियों का निर्माण करना।
- सदस्यों/सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय, तकनीकी, विस्तार एवं विपणन सेवायें प्रदान करना।
- स्वयं व अपनी सदस्य समितियों की ओर से आवश्यकता अनुसार कृषि आदानों, कृषि औजारों/ मशीनों व अन्य सहायक वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण व विपणन संबधी कार्य करना।

MISSION

To enhance the socio-economic status of the people through collective action for Sustainable Natural Resources Management.

VISION

Assisting the poor to enhance their capabilities for attaining their aspirations; Creating enabling environment for the poor to access new opportunities and develop & enhance resource base essential for leading a dignified life.

OBJECTIVES

- Wasteland development for ecological balance and engendering sustainable rural livelihood resources.
- Socio-economic development of the rural community through Integrated Natural Resources Management and Farming System Approach.
- Creating people-centered, gender focussed sustainable community institutions/ cooperatives to ensure community participation and women empowerment.
- To provide Financial, Technical, Extension and Marketing services to members / community institutions.
- To undertake production, processing, distribution and marketing of need based Agricultural Inputs, Agricultural Implements / Machineries and other allied articles on its own or on behalf of its members.

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

अध्यक्ष / Chairman
गुरु प्रसाद त्रिपाठी
G. P. Tripathi

उपाध्यक्ष / Vice-Chairman
दया कृष्ण भट्ट
D. K. Bhatt

निदेशक / Director
अरबिन्द राय
A. Roy

निदेशक / Director
लखन सिंह
Lakhan Singh

निदेशक / Director
नारायण लाल अहीर
Narayan Lal Ahir

निदेशक / Director
शान्ता राव
Shanta Rao

निदेशक / Director
बदरुल हसन
Badrul Hassan

मुख्य कार्यकारी / Chief Executive
डा. के. जी. वानखेड़े
Dr. K.G. Wankhede

पूर्व अध्यक्ष / EX-CHAIRMEN

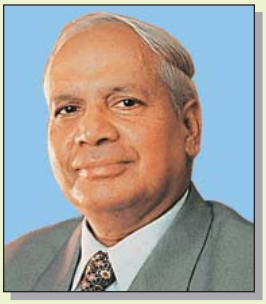

डा. वी. कुमार
(अक्टूबर 22, 1993 - फरवरी 11, 2003)
Dr. V. Kumar
(Oct. 22, 1993 - Feb. 11, 2003)

दया कृष्ण भट्ट
(फरवरी 12, 2003 - जून 25, 2009)
D. K. Bhatt
(Feb. 12, 2003 - June 25, 2009)

पूर्व मुख्य कार्यकारी / EX-CHIEF EXECUTIVES

स्व. डा. ओ. पी. गौड़
(अक्टूबर 22, 1993 - अगस्त 31, 2000)
Late Dr. O. P. Gaur
(Oct. 22, 1993 - Aug. 31, 2000)

अशोक आलम्बेन
(सितम्बर 01, 2000 - सितम्बर 03, 2002)
Ashok Alambain
(Sept. 01, 2000 - Sept. 03, 2002)

स्व. डा. पी. एस. मरवाहा
(सितम्बर 03, 2002 - सितम्बर 02, 2008)
Late Dr. P. S. Marwaha
(Sept. 03, 2002 - Sept. 02, 2008)

प्रवीण अग्रवाल
(कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी)
(सितम्बर 03, 2008 - अक्टूबर 13, 2008)
Praveen Agarwal
(Acting Chief Executive)
(Sept. 03, 2008 - Oct. 13, 2008)

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट को-आपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) वर्ष 1993 में अस्तित्व में आई, यद्यपि, इसका कार्य 1986-87 में पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। इसकी प्रवर्तक संस्था, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में प्रक्षेत्र वानिकी के द्वारा पर्यावरण संतुलन एवं बंजर भूमि विकास का कार्य प्रारम्भ किया था, जिसे, देश में आगे बढ़ाने एवं ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ समन्वित करने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया था।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ जलग्रहण प्रबंधन, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा, आजीविका, बीज उत्पादन, कृषि आदान आपूर्ति एवं सार्वभौमिक अवधान आदि के द्वारा अपने पोर्टफोलियो के विविधिकरण तथा विस्तारीकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। जिसमें समुदाय की उभरती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहभागी पद्धतियों को अपनाया गया।

पिछले एक दशक से, संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर उत्तराखण्ड, उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में भी निरन्तर रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। संस्था, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के अन्तर्गत 14 राज्यों के 9,410 से भी अधिक गांवों में कार्यरत है तथा इसने अब तक 220 करोड़ रुपये से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदाय करने के लिए बीज उत्पादन और विपणन कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया है।

वैधानिक स्थिति

संस्था का पंजीयन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम (एम.एस.सी.एस.), 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002) के अंतर्गत सहकारिता एवं कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 22, 1993 को किया गया। इसकी पंजीयन सं. L-11015/6/93-L & M है।

श्री जी.पी. त्रिपाठी, अध्यक्ष, आईएफएफडीसी की 20वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए

IFFDC Ltd.

Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (IFFDC) came into existence formally in 1993 although its work had begun as early as in 1986-87. Its promoter, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), had launched programmes of eco-restoration and wasteland development through farm forestry in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan and these programmes were subsequently handed over to the IFFDC for being scaled up and integrated with rural livelihood development and poverty alleviation programmes in the country.

IFFDC has diversified its portfolio and has broadened its focus to include in addition to Farm Forestry and Climate Change, activities such as Watershed Management, Nutritional and Economic Security, Livelihoods, Seed Production, Agri-Input Supply, Cross Cutting Interventions etc. This has been done by adopting approaches that are participatory in nature and designed to cater to the emerging and evolving needs of the community.

Over the past decade, IFFDC has also expanded its territorial scope of action and started sustained operations in the States of Uttarakhand, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Himachal, Haryana and Punjab. With its presence in more than 9,410 villages across 14 States covering all the agro-climatic zones, it has so far implemented rural development projects worth more than Rs.220 crore.

In addition to the above programmes, IFFDC has also started a Seed Production and Marketing Programme to provide quality seed to the farmers of rural India.

Legal Status

IFFDC was registered on 22nd October, 1993 by the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India as a Multi State Cooperative Society under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 1984 (subsequently under the MSCS Act 2002) with Registration No. "L – 11015/6/93 – L & M".

Delegates from member cooperatives participating in the 20th Annual General Meeting

सदस्यता

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), राज्य सहकारी संघ, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस), इसकी सदस्य हैं। 31 मार्च, 2014 को 173 सहकारी समितियाँ, आई.एफ.एफ.डी.सी. की सदस्य हैं।

शेयर पूँजी

100 करोड़ रू. की अधिकृत शेयर पूँजी के सापेक्ष 31-03-2014 तक इसकी अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी 13.17 करोड़ रुपये है, जो निम्नानुसार है :-

प्रत्येक शेयर का मूल्य (₹)	शेयर धारक	शेयरों की संख्या
50,000	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड	2,507
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	8
10,000	उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1
	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	1
1,000	प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ लिमिटेड एवं प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ लि.	5,999

गवर्नेंस

ग्रामीण समुदाय के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध, आई.एफ.एफ.डी.सी. की गवर्नेंस संरचना सहकारिता के मूल्यों एवं सिद्धांतों के उच्चस्तरीय मानकों को ध्यान में रखते हुए बहुराज्यीय सहकारी सिमिति अधिनियम/नियमावली 2002 के प्रावधानों के अनुरूप गठित की गयी। इसके आन्तरिक प्रबन्धन एवं कार्य, इसके उपनियमों के अनुसार ही संचालित किये जाते हैं।

संस्था के ढाँचें में व्यवसाय पारदर्शिता, आन्तरिक नियंत्रण एवं समीक्षा प्रक्रियाएं समाहित हैं। समिति की नीतियाँ एवं कार्य पद्धतियाँ न केवल सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करती हैं बल्कि, इसके भागीदारों के सर्वोच्च हितों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल में विविधि पृष्ठभूमि वाले, जमीनी स्तर के निर्वाचित सहकारगणों के साथ-साथ संस्थाओं के प्रतिनिधित्व हेतु नामित सदस्य हैं जिनसे अंशधारक सदस्यों की आवश्यकता एवं हितों की पूर्ति सुनिश्चित होती है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के क्रम में निदेशक मण्डल में एक स्थान महिला निदेशक के लिए आरक्षित किया गया है।

क्रियान्वयन स्तर पर आई.एफ.एफ.डी.सी., सामाजिक एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विविध क्षेत्रों जेसे कृषि, सहकारिता, वित्त, तकनीकी, विपणन एवं सामान्य प्रबंधन में दक्ष तथा उच्च अनुभव रखने वाले प्रबंधकों के माध्यम से कार्य करती है।

Membership

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. (IFFCO), National Co-operative Development Corporation (NCDC), State Cooperative Federations, Primary Farm Forestry Co-operative Societies (PFFCS) and Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS) are members of the IFFDC. As on March 31, 2014, 173 Cooperative Societies are its members.

Share Capital

Against an authorized share capital of Rs.100 crore, the IFFDC's subscribed and paid-up capital as on 31-03-2014 is Rs.13.17 crore illustrated as under:

Value of Each Share (₹)	Shareholders	No. of Shares
50,000	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited	2,507
	National Cooperative Development Corporation	8
10,000	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.	1
	Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd.	1
1,000	Primary Farm Forestry Cooperative Societies Ltd. and Primary Livelihood Development Cooperative Societies Ltd.	5,999

Governance

Committed to the integrated development of India's rural community, the IFFDC governance structure is designed adhering to the highest standards of Cooperative Values and Principles and is in conformity with the provisions of the Multi State Cooperative Societies Acts & Rules, 2002. Its internal management and functions are guided by its Bye-laws.

With business systems and processes in place that are designed for transparency, internal control and enabling adequate review, IFFDC's policies and practices are not only consistent with current statutory requirements, but also reflect its commitment to ensure the best interests of its members/stakeholders.

Board of Directors

Board of Directors has members from diverse backgrounds and is constituted of grassroots based elected co-operators as well as nominated and co-opted members, who represent institutions that cater to the need and interests of its shareholders. One seat on the Board has been reserved for an elected woman Director to represent the constituency of women.

On its operational front, IFFDC functions through skilled managers, who have wide experience & expertise in diverse fields related to social and rural development, such as agriculture, cooperatives, finance, technology, marketing and general management.

हमारा दृष्टिकोण

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति में तेजी लाना एवं ग्रामीण समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों का उत्थान करना है। इसकी यह धारणा है कि, ग्रामीण विकास, इन समुदायों की प्रत्येक स्तर पर सम्पूर्ण भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो इसकी समग्र सहभागी पहुँचों में समाहित है तथा क्षमताओं के निर्माण में विशेष बल के साथ इसके विविध पोर्टफोलियो में अन्तःनिर्मित है। समुदायों को परस्पर सहबद्ध रखने और मुख्य रूप से इसके अवधानों को दीर्घावधि तक चिरन्तर बनाये रखने के लिए सहकारिता के मार्ग पर आधारित संस्थागत निर्माण करना ही इसके कार्यक्रमों का प्रमुख आधार रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने विकास एवं सम्बन्धित धारणाओं की उभरती आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप प्रादुर्भावित विशिष्ट मुद्दों पर कार्य करने के लिए तदानुसार अपनी रणनीतियाँ बनाई। संस्था के पिछले दो दशकों के अर्जित अनुभवों ने इसके नये क्रियाकलापों को निश्चित किया। जिससे, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्था को अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में मदद मिली।

प्रारंभिक तौर पर प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को सम्बोधित कर वर्तमान समय में वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समयानुसार विभिन्न पोर्टफोलियों को अपनी कार्यप्रणाली में सम्मिलित करते हुए अपने ग्रामीण विकास के मुद्दों का विस्तारीकरण किया जिसमें अधिकांशतया इसके ग्रामीण विकास की कार्यसूची में से उभर कर आये हैं जो निम्नानुसार हैः

- प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन
- जलग्रहण प्रबन्धन एवं जलवायु परिवर्तन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)
- आदिवासी व सीमान्त समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)
- चिरन्तर ग्रामीण आजीविका विकास
- परामर्श कार्यक्रम
- सार्वभौमिक अवधान (सामुदायिक संस्थाएं, जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण)
- बीज एवं कृषि-आदानों की आपूर्ति

OUR APPROACH

IFFDC's aim is to trigger development in rural areas and enhance livelihood options of rural communities. Its conviction that this can be best achieved only with the total involvement of the communities that it works amongst, has engendered its overall participatory approach along with emphasis on capacity building that is in-built in its numerous portfolios. For holding communities together, and importantly, to ensure among other things, long term sustainability of its interventions, Institution Building, following the cooperative route, has been a major plank of its programmes.

IFFDC has accordingly framed its strategies to deal with specific issues arising as a corollary to the fast growing development needs and the aligned imperatives. Its wealth of accumulated experience of the past two decades has in turn helped to create for it a distinct niche in the rural development arena.

Starting out primarily as a Farm Forestry Cooperative that would address the issue of Climate Change, which had at the time caught the attention of the global community, IFFDC has over the time expanded its areas of concern to include several portfolios, most of these emerging out of its primary agenda of rural development are as follows:

- Farm Forestry and Climate Change.
- Watershed Development and Climate Change (Ecological Resilience).
- Nutritional and Economic Security for Tribal and Marginalised Communities (NEST).
- Sustainable Rural Livelihood Development.
- Consultancy Programme.
- Cross Cutting Interventions (Community Institutions, Gender Mainstreaming & Women Empowerment, Capacity Building).
- Seed and Agri-inputs Supply

परियोजनाओं का विवरण

(अ) इफको द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. प्रक्षेत्र वानिकी परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड)
2. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.), उडीसा
3. समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आर.डी.पी.), शिवगंगई (तमिलनाडु)
4. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.), बाँकुरा (पश्चिम बंगाल)
5. मृदा जीर्णोद्धार तथा उत्पादकता वृद्धि परियोजना - उन्नाव (उत्तर प्रदेश)
6. समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना - हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)

(ब) नाबार्ड द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. जल ग्रहण विकास परियोजनाएं :- सागर एवं छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश), कुई, कुकदर, खुर्रभाटा (छत्तीसगढ़), डी.बी. थण्डा, दम्मनापेट, गोविन्दपल्ली, जिला निजामाबाद (आन्ध्रप्रदेश), प्रतापगढ़ (राजस्थान)
2. वाडी परियोजनायें :- प्रतापगढ़ (राजस्थान), कवर्धा एवं बिलासपुर (छत्तीसगढ़), सागर एवं छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश), बांकुरा (पश्चिमी बंगाल), आदिलाबाद (आन्ध्रप्रदेश) तथा पलामू (झारखंड)
3. स्वयं सहायता समूह एवं किसान क्लब संवर्द्धन परियोजना :- सागर, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), गुमला (झारखंड)

(स) राज्य सरकारों द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. समग्र जलग्रहण विकास परियोजनाऐं, रीवा एवं छतरपुर (मध्य प्रदेश)।
2. पश्चिमी राजस्थान में गरीबी शमन परियोजना (एम पावर) - सांचोर (राजस्थान)

(द) अन्य ऐजेन्सियों द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन एवं दलहन विकास परियोजना, लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी), नई दिल्ली के सहयोग से।
2. भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड (बी.ओ.आर.एल.) द्वारा सहायतित बीना, मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण एवं रखरखाव परियोजना।
3. रूडा जयपुर की सहायता से उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर में विशेष एस.जी.एस.वाई. की रूडा परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारों को मुख्य धारा से जोड़ना।

(य) नई परियोजनाएं

1. पश्चिमी बंगाल के जिला बांकुरा में 1000 परिवारों के लिए दो वाडी विकास परियोजनायें।
2. राजस्थान के जिला उदयपुर में 2000 हेक्ट. पर दो जलग्रहण परियोजनायें (क्षमता विकास फेस)।
3. राजस्थान के हाडौती क्षेत्र में 500 शिल्पकार परिवारों के लिए कोटाडोरिया क्लस्टर विकास परियोजना।
4. राष्ट्रीय सब्जी पहल के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (शिमला, सिरमौर, सोलन), हरियाणा (पंचकुला) एवं दलहन विकास के अन्तर्गत मध्य प्रदेश (सागर एवं सतना) किसान उत्पादक संगठन परियोजनायें।

DETAILS OF PROJECTS

(A) IFFCO Supported Projects

1. Farm Forestry Projects (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand).
2. Rural Livelihood Development Project (RLDP), Orissa.
3. Integrated Rural Development Project (IRDP), Sivagangai (Tamil Nadu).
4. Rural Livelihood Development Project (RLDP), Bankura (West Bengal).
5. Soil Rejuvenation and Productivity Enhancement Project – Unnao (Uttar Pradesh)
6. Integrated Rural Development Project – Haridwar, (Uttarakhand).

(B) NABARD Supported Projects

1. Watershed Development Projects :- Sagar and Chhindwara (Madhya Pradesh), Kui, Kukdar, Khurubhata (Chhattisgarh), D.B.Thanda, Dammanapet, Govindapally in Nizamabad (Andhra Pradesh), Pratapgarh (Rajasthan).
2. Wadi Projects:- Pratapgarh (Rajasthan); Kawardha & Bilaspur (Chhattisgarh), Sagar and Chhindwara (Madhya Pradesh.), Bankura (West Bengal), Adilabad (Andhra Pradesh), Palamu (Jharkhand)
3. Self Help Group and Farmers Club Promotion Project :- Sagar, Chhindawara (Madhya Pradesh), Bilaspur (Chhattisgarh), Gumla (Jharkhand).

(C) Projects Supported by State Governments

1. Integrated Watershed Management Projects at Rewa and Chhattarpur (Madhya Pradesh).
2. Mitigating Poverty in Western Rajasthan (MPOWER) – Sanchore (Rajasthan)

(D) Projects Supported by Other Agencies

1. National Vegetable Initiative and Pulses Development Programme supported by Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC), New Delhi
2. Up Keeping and Maintenance of Plantation supported by Bharat Oman Refinery Limited (BORL), Bina, Madhya Pradesh
3. Main Streaming 'Rural Artisans' under SGSY Special RUDA Project Udaipur, Rajsamand, Dungarpur supported by Rural Non-Farm Development Agency (RUDA), Jaipur.

(E) New Projects Mobilised

1. Two Wadi development in West Bengal distt. Bankura for 1000 familiese
2. Two Watershed Management in Rajasthan Distt. Udaipur for 2000 Ha.(Initially Capacity Building Phase)
3. Development of Kotadoriya cluster in Hadoti region of Rajasthan for 500 artisan families.
4. FPO formation under NVI in Himachal Pradesh (Shimla, Sirmaur, Solan), Haryana (Panchkula) and Under Pulse Development in Madhya Pradesh (Sagar and Satna).

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय सहकार बन्धुओं,

आपकी संस्था की वर्ष 2013-14 की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी समिति ने ग्रामीण समुदाय को मार्गदर्शित करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर लाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल कर, उनके सम्मान और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करते हुये, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने में समर्पित गौरवशाली 21 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं।

संस्था के कर्मचारियों के सतत प्रयासों के कारण सरकार एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से परियोजनाऐं लाने में संस्था ने सफलता प्राप्त की है। आप सभी को ज्ञात है कि, आपकी समिति द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों गतिविधियों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मैं पिछले वर्ष की विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

आपकी समिति ने बीज उत्पादन कार्यक्रम में वृद्धि कर किसानों को गुणवतायुक्त बीज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे निसंदेह उत्पादकता में वृद्धि एवं समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा में आवश्यक रूप से दीर्घकालिक अनूकूल प्रभाव होगा। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि बहुत सी नयी परियोजनाओं और निरंतर चल रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनके चिरन्तर संचालन में सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ आपकी समिति को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर के रुप में विभिन्न राज्यों में की जा रही विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की मॉनिटरिंग करने हेतु एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियोवार प्रगति इस प्रकार है :-

DIRECTORS' REPORT

Honourable Co-operators,

It is my great privilege to place before you the 21st Annual Report of your Society for 2013-14. I would like to begin by congratulating each and every one of you on the completion of 21 glorious years by your society dedicated to guiding the rural community, metaphorically speaking, out of 'Darkness' into 'Light', or in other words, bringing them out of poverty to self respect and the ability to shape their destinies, by equipping them with skills and building their capacity.

This was possible only due to sincere efforts by your Society's dedicated staff, their will and perseverance to mobilise projects from different funding agencies as well as Government. You are all aware of the good work being done by your Society across the country and covering a wide range of activities. I would like to highlight a few special areas of achievements in the last year that are noteworthy.

A major contribution has been the upscaling of the Seed Production Programme to make available quality seed to farmers, which will undoubtedly go a long way towards improving productivity and impact favourably for food security. It is also a matter of great pride for me to inform you that along with various new & ongoing projects that it has been successful in initiating and sustaining, your Society has been assigned a significant responsibility of monitoring various Government programmes and schemes being implemented in different states as a National Level Monitor (NLM) by the Rural Development Ministry, Government of India. Portfolio-wise progress during the year is as follows :-

प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य कार्यक्रम प्रक्षेत्र वानिकी, किसानों की व्यक्तिगत, ग्राम पंचायत तथा राजकीय राजस्व बंजर व सीमांत भूमियों पर सहभागी वानिकी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने तथा कार्बन क्रेडिट के नकदीकरण पर केंद्रित है। संबंधित समुदायों को प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (पी.एफ.एफ.सी.एस.) के माध्यम से संगठित किया गया है। ये समितियां, सामुदायिक वनों को प्रबन्धन चिरंतर आधार पर करने में मुख्य सामुदायिक संस्था के रूप में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी., आवश्यक तकनीकी, वित्तीय, क्षमता निर्माण, संबंध विकसित करने, विपणन एवं स्त्रोत जुटाने से संबंधित आदानों के लिए पी.एफ.एफ.सी.एस. की सहायता करती है। इसके अवधानों के फलस्वरूप, 500 से अधिक गांवों में न सिर्फ हरितिमा विकसित हुई है बल्कि, बंजर भूमि भी पुनरक्षित हुई है। विद्यमान वनों से आर्थिक लाभ वर्तमान में केवल चुनिंदा कटाई घास एवं लघु वनोपज आदि तक सीमित है जिसे समुदाय के लाभ हेतु अन्य वातावरणीय सेवाओ के माध्यम से और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के समग्र दृष्टिकोण का ध्यान अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे अवैध कटाई, हितधारकों के आर्थिक लाभ के लिए बेहतर वनोपज प्रदान करने, इन वनों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के व्यवसाय जैसे अन्य वैकल्पिक अवसरों तथा इस भूमि के उपयोग अधिकारों को पुनः परिभाषित करने आदि पर भी केन्द्रित है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वृक्षारोपण हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों में कई दशकों से वृहद स्तर पर खाली पड़ी हुई बंजर भूमि की पहचान कर अधिग्रहित की। यह बंजर भूमि, राजस्थान में ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में निजी कृषकों तथा मध्य प्रदेश में राजस्व के स्वामित्व वाली है।

वानिकी समिति सदस्यों के साथ समिति प्रबंधन पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी

FARM FORESTRY AND CLIMATE CHANGE

IFFDC's flagship programme of Farm Forestry focuses on mitigating climate change effects and encashing carbon credits through developing participatory forestry on waste and marginalised lands belonging to individual farmers, village panchayats and Government. The concerned communities are organised into Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS), designed as the key community institutions to manage and maintain the developed community forests, on a sustainable basis.

IFFDC supports the PFFCS with the necessary technical, financial, capacity building, networking, marketing and resource mobilisation inputs. As a result of its intervention, green cover has not only been improved in more than 500 villages, but degraded lands have also been restored. Economic returns from existing forests, presently restricted to selective felling, grasses and Minor Forest Produce (MFPs) etc., however need to be accelerated for other environmental services/benefits to the community.

The integrated approach of the IFFDC also led to attention being given to related activities such as control of illegal felling, prevention of encroachment, better forest yield for improving economic returns to the stakeholders, options such as trading of carbon credits generated through these forests and defining the usufruct rights of these lands, etc.

PROGRESS

IFFDC identified for afforestation large tracts of wasteland, which had been lying almost barren for decades in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand. These acquired wastelands are Panchayat lands in Rajasthan, individual lands in Uttar Pradesh & Uttarakhand and Revenue land in Madhya Pradesh.

Agro-Forestry model developed at farmers field

वर्ष के दौरान

- *कुल 849 हेक्टेयर (388 हैक्ट. उत्तर प्रदेश, 51 हेक्टेयर उत्तराखण्ड, 60 हेक्टेयर मध्य प्रदेश तथा 350 हेक्टेयर राजस्थान) क्षेत्र पर वनीकरण किया गया। पौध रोपण की लागत कम करने एवं जीवित दर बढ़ाने हेतु राजस्थान में प्रोसोपिस के बीजों की सीधे बुवाई की गयी है।*
- *8.68 लाख पौधे (3.98 लाख उत्तर प्रदेश, 0.65 लाख मध्य प्रदेश, 3.85 लाख राजस्थान एवं 0.2 लाख फलदार पौधे उत्तराखंड में) विभिन्न समितियों में रोपित किये गये हैं। जिनमें मुख्यतः नीम, प्रोसोपिस, शीशम, सागवान, बांस, अमरूद एवं आम आदि हैं।*
- *विभिन्न वानिकी समितियों की 103 वार्षिक आम सभायें तथा 1037 कार्यकारी बैठकों का आयोजन किया गया। वानिकी समितियों के लिए 4 एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन किया गया जिसमें 100 सदस्यों ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया।*
- *7 स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया।*

प्रारंभ से अब तक

- *4 राज्यों में विकसित कुल 28,452 हैक्टेयर (12,283 हैक्टेयर उत्तर प्रदेश, 9,508 हैक्टेयर राजस्थान, 6,516 हैक्टेयर मध्य प्रदेश तथा 145 हैक्टेयर उत्तराखण्ड में) वृक्षारोपण का प्रबंधन वानिकी समितियों द्वारा किया जा रहा है।*
- *130.99 लाख पौधों (53.85 लाख उत्तर प्रदेश, 34.65 लाख राजस्थान, 41.91 लाख मध्य प्रदेश एवं 0.58 लाख उत्तराखण्ड) का प्रबन्धन 148 समितियों द्वारा किया जा रहा है। इस जैव विविधतापूर्ण जंगल में यूकेलिप्टस (यूकेलिप्टस स्पीशीज), सागवान (टेक्टोना ग्रेन्डिस), बबूल (अकेसिया नीलोटिका), सुबबूल (ल्यूसिना ल्यूकोसिफीलिया), शीशम (डलबर्जिया सिसू), नीम (अजेडिरेक्टा इंडिका), जट्रोफा (जट्रोफा कर्कस), करंज (पोंगामिया पिन्नाटा) तथा बांस (बंबूसा स्पीशीज) आदि प्रजातियों के पौधे हैं।*
- *148 वानिकी समितियों में नए वृक्षारोपण एवं मौजूदा वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।*

परिणाम

- प्राथमिक वानिकी समितियाँ पर्यावरण संरक्षण और जलाऊ लकड़ी, चारा एवं अन्य सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक प्रमुख संस्था के रूप में विकसित हो रही है।
- समस्याग्रस्त भूमियां (क्षारीय, लवणीय, बीहड़ और जल भराव भूमि) अब कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित होने से ये एक उत्पादक सम्पत्ति के रूप में सिद्ध हो रही है।
- कृषि वानिकी गतिविधियों द्वारा पारिस्थतिकीय संतुलन बनाये रखने में मदद हो रही है। आई.एफ.एफ.डी.सी. के हरित संपदा कार्य से लगभग 14.27 टन प्रति हेक्ट. प्रति वर्ष कार्बन संचयन करने में मदद हो रही है।

कार्बन क्रेडिट के लिए उठाये गये कदम

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने विकसित वनों से वातावरण की कार्बन को अवशोषित करने से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को प्रमाणित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की वानिकी समितियों में विकसित 222 हेक्ट. वनों का अपनी परामर्शदायी संस्था मैसर्स इमरजेंट वेंचर ऑफ इण्डिया प्रा. लि. (ई.वी.आई) की सहायता से परियोजना विवरण दस्तावेज (पी.डी.डी.) मय जी.आई.एस. मानचित्र के तैयार कर सत्यापित कार्बन मानकों के तहत पंजीकरण कराया गया है। मान्यकरण व सत्यापन के लिए प्राधिकृत एजेंसी मैसर्स रेनफोरेस्ट अलायन्स, न्यूयार्क द्वारा परियोजना का अंकेक्षण किया गया तथा यह सत्यापित किया कि वर्ष 2009 से 30 वर्षों में कुल 1,69,554 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होंगे। कार्बन क्रेडिट/इकाइयों के ऑनलाईन ट्रैडिंग के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपना खाता एन.वाई.एस.ई. ब्ल्यू, वी.सी.एस. रजिस्ट्री न्यूयार्क में खोल लिया है।

During the Year

- *849 ha.area (388 ha in Uttar Pradesh, 51 ha in Uttarakhand, 60 ha in Madhya Pradesh and 350 ha in Rajasthan) has been covered under plantation. To reduce the cost of plantation and increase survival of plants, direct seed sowing of Prosopis has been adopted in Rajasthan.*
- *8.68 lakh plants (3.98 lakh in Uttar Pradesh, 0.65 lakh in Madhya Pradesh, 3.85 lakh in Rajasthan and 0.2 lakh fruits plants in Uttarakhand) have been planted by different PFFCS. Major species are Neem, Prosopis, Eucalyptus, Shisham,Teak , bamboo , Guava, Aonla and Mango etc.*
- *103 Annual General Body Meetings and 1037 Executive Committee Meetings were organised at various PFFCS and 4 Exposure tours were organised for PFFCS members in which 100 members visited different places.*
- *7 Health Camps were organised.*

Since Inception

- *Total plantation on 28,452 ha. area (12,283 ha. in Uttar Pradesh, 9,508 ha. in Rajasthan, 6,516 ha. in Madhya Pradesh and 145 ha in Uttarakhand) is being managed by PFFCS in four states.*
- *130.99 lakh trees (53.85 lakh in Uttar Pradesh, 34.65 lakh in Rajasthan, 41.91 lakh in Madhya Pradesh and 0.58 lakh in Uttarakhand) are being managed by 148 PFFCS . The bio-diversified forest cover includes Eucalyptus (Eucalyptus species), Teak (Tectona grandis), Babool (Acacia nilotica) Subabool (Leucaena leucocephala) Shisham (Dalbergia sisoo), Neem (Azadirachta indica) Jatropha (Jatropha curcus), Karanj (Pongamia pinnata), Bamboo (Bambusa strictus) etc.*
- *148 PFFCS were technically and financially supported to develop new forest and protect existing forests.*

Outcome

- ➢ *PFFCS are serving as nodal agencies for environment up-gradation and catering to fuel wood, fodder and other needs of the community.*
- ➢ *Problematic lands (sodic, saline, ravines and water logged, etc) are now converted into cultivable lands and have proved to be productive assets.*
- ➢ *Farm forestry activities have helped to bring ecological balance. The green cushion facilitated by IFFDC has resulted in an estimated present net carbon sequestration of 14.27 MT per ha/year.*

Steps forward for carbon credits

IFFDC has gone a step ahead for getting certified the carbon credits being generated by its developed forests by absorbing atmospheric carbon. The Project Description Document (PDD) including GIS mapping of 222 ha plantation developed in the PFFCS of Uttar Pradesh has been prepared and registered with the help of Consulting Firm, M/s Emergent Venture India Pvt. Ltd. (EVI) under Verified Carbon Standard (VCS). The accredited Validation and Verification Agency, M/s Rainforest Alliance, New York has audited the project and validated the claim that the project will generate 1,69,554 carbon credits during the period of 30 years w.e.f 2009. For online trading of the carbon credits/units, IFFDC has opened an account with the NYSE Blue, VCS Registry, New York.

जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय स्कन्दन)

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने प्रक्षेत्र वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में काफी समय पूर्व ही इस गतिविधि को समाहित करने एवं अन्य विषयक अवधानों जैसे जल संसाधन विकास आदि के महत्व को मान लिया था। आई.एफ.एफ.डी.सी. को विशेषतः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की जेंडर केंद्रित आजीविका उत्थान के लिए जलग्रहण कार्यक्रम का बहुत अनुभव है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम जलग्रहण कमेटी तथा जल उपयोग कमेटियां जैसी सामुदायिक संस्थायें विकसित की गयीं। जल एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में समुदाय के लिए पारिथितिकीय प्रतिस्कंदन निर्माण हेतु इस गतिविधि में भू-उपयोग योजना एवं विकास तथा अन्य आजीविका अर्जन से संबंधित गतिविधियों के एक व्यापक समूह को क्रमबद्ध तरीके से समाहित किया गया है।

जलग्रहण का मुख्य उद्देश्य, भूमि व जल संसाधनों को संरक्षित व पुनर्स्थापित करना जिससे, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिस्कंदन विकसित हो तथा इन क्षेत्रों में खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस हेतु, आई.एफ.एफ.डी.सी. जल संसाधनों के क्षरण को पुर्नस्थापित करने के लिए अन्य संस्थाओं तथा सीधे नाबार्ड से एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं से आभिमुखीकरण द्वारा संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

प्रगति

वर्तमान में इसके द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान में 38,592 हैक्टेयर क्षेत्र में 14 जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें मुख्य जोर, चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं जैसे ग्राम जलग्रहण समितियों (वी.डब्ल्यू.सी.) का विकास एवं परियोजना चक्र के सभी स्तरों में जेन्डर समानता को सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण समुदाय की क्षमता निर्माण पर दिया गया।

WATERSHED MANAGEMENT (Ecological Resilience)

Very early on in its Farm Forestry and Climate Change crusade, IFFDC recognised the importance of integrating other thematic interventions like Water Resource Development into this activity. In particular, the IFFDC's experience of its watershed programme for improving gender focused rural livelihoods of communities through natural resource management is noteworthy. Village Watershed Committees and Water Users Committees are developed for implementing this programme. Focusing on providing Water and Food Security, a comprehensive set of activities related to land use planning and development and other livelihood generation activities has been systematically integrated for building up the 'Ecosystem Resilience' of the community.

The purpose of watershed development is to rehabilitate and conserve land and water resources in order to develop resilience towards climate change to ensure food and livelihood security. For this, the IFFDC has joined hands with other agencies and is mobilizing resources directly from NABARD and through convergence with various Government agencies for the restoration of depleting water resources.

PROGRESS

Presently, it is implementing 14 watershed projects on 38,592 ha area in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Rajasthan. The focus is on building capacities of the rural community by developing sustainable community institutions like Village Watershed Committee (VWC) and ensuring gender equity in all stages of the project cycle.

परियोजना विवरण

सहायक संस्था	राज्य	जिला	कुल क्षेत्र (हेक्ट.)	उपचारित क्षेत्र (हेक्ट.)
नाबार्ड	छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	3,207	2,609
	मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा	1,452	1,185
	राजस्थान	प्रतापगढ़	2,067	1,302
	आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद	5,375	1,406
राज्य सरकारें	म.प्र. (मनरेगा)	भोपाल, श्योपुर, छतरपुर	15,000	3,417
	म.प्र. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	छतरपुर, रीवा	11,491	3,397
	कुल		**38,592**	**13,316**

वर्ष के दौरान

- *प्रभावी मृदा एवं जल संरक्षण विधियाँ जैसे - खेत की मेड़बंदी, लगातार समोच्च खाई, (सी.सी.टी.), लूज स्टोन चेकडेम (एल.एस.सी.डी.), नाली वंधान और चैकडेम द्वारा 3,079 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है।*
- *जल संसाधन विकास हेतु 53 स्टाप डेम/एनीकट, 49 तालाब गहरीकरण और 3 कुआँ निर्माण का कार्य किया गया है।*
- *जलग्रहण क्षेत्रों में 15,400 वानिकी पौधे की विभिन्न प्रजातियों का रोपण किया गया है।*
- *विभिन्न पहलुओं पर 52 प्रशिक्षण एवं 1 एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया।*

प्रारम्भ से अब तक

- *प्रभावी मृदा एवं जल संरक्षण विधियाँ जैसे - खेत की मेड़बंदी, लगातार समोच्च खाई, (सी.सी.टी.), लूज स्टोन चेकडेम (एल.एस.सी.डी.), नाली वंधान और चैकडेम द्वारा 13,316 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है।*
- *जल संसाधन विकास हेतु 103 स्टाप डेम/एनीकट, 85 तालाब गहरीकरण और 26 कुआँ निर्माण का कार्य किया गया है।*
- *जलग्रहण क्षेत्र में वानिकी बहुउद्देशीय प्रजातियों के 2,05,007 पौधों का रोपण किया गया है।*

परिणाम

- कुओं में पानी के स्तर में वृद्धि हुई तथा किसान अपनी दूसरी फसल लेने में सफल हुए, जिससे अधिक आमदनी हुई है।
- मृदा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के करने से कृषि योग्य भूमि में अतिरिक्त क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हुई है।
- विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण की गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र के भूमिहीन कृषक एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं।

PROJECT DETAILS

Supporting Agency	State	District	Total Area (ha)	Treated Area (ha)
NABARD	Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	3,207	2,609
	Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara	1,452	1,185
	Rajasthan	Pratapgarh	2,067	1,302
	Andhra Pradesh	Adilabad	5,375	1,406
State Govt	MP (MGNREGA)	Bhopal, Sheopur, Chhattarpur	15,000	3,417
	MP (IWMP)	Chhattarpur, Rewa	11,491	3,397
	Total		**38,592**	**13,316**

During the year

- *3,079 ha area has been treated with effective soil & water conservation measures like Farm Bunding (FB), Continuous Contour Trench (CCT), Loose Stone Check Dam (LSCD), Gully Plugs (GP) and Check Dam (CD).*
- *53 stop dams/anicuts, 49 ponds deepening and 3 wells construction have been undertaken for water resource development.*
- *15,400 forestry plants of different species have been planted in the watershed areas.*
- *52 Training programmes and 1 Exposure visits on different issues have been organised.*

Since Inception

- 13,316 *ha area has been treated with effective soil water conservation measures like Farm Bunding (FB), Continuous Contour Trench (CCT), Loose Stone Check Dam (LSCD), Gully Plug (GP) and Check Dam (CD).*
- *103 Stop Dams/Anicuts, 85 Ponds Deepening and 26 Wells Construction have been undertaken for Water Resource Development.*
- *2,05,007 saplings of forestry species have been planted in the watershed areas.*

Outcome

- Increase of water table of the wells has been observed and farmers are able to harvest their second crop successfully leading to more returns.
- Additional area has been brought under cultivation by adopting various soil conservation measures.
- Landless farmers and women have been endowed with employment opportunities in the area through various soil moisture conservation activities.

जनजातीय व सीमान्त समुदाय के लिए पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा (नेस्ट)

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा "जनजातीय व सीमान्त समुदाय को पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा" प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. (नाबार्ड) की आर्थिक सहायता से लघु फलोद्यान/वाडी विकास के लिए परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना में, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषणता एवं इन समस्याओं के उचित समन्वित समाधानों को ज्ञात करने हेतु वृहद परिदृश्य में देखने की आवश्यकता को समाहित किया गया है। इन परियोजनाओं में, ग्रामीण परिवारों को आत्मीयता वाले समूहों जिसे 'वाडी टुकड़ी' कहा गया में संगठित कर तथा उनकी चयनित भूमि में फलदार वृक्ष लगाने के साथ-साथ अन्तः कृषि एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित करने के क्रम में क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गयी। इसमें परिवार के उपभोग के अलावा 'वेल्यू चेन' का निर्माण कर उत्पादन को उच्च स्तर पर बढाने पर बल दिया गया। जिससे, आय एवं आजीविका में वृद्धि होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आय संवर्द्धन से लेकर भूमि उत्पादकता में वृद्धि करने तक समन्वित ग्रामीण विकास हेतु विविध गतिविधियाँ भी शामिल की गयी हैं।

प्रगति

वाड़ी कार्यक्रम नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से संचालित किया जा रहा है। 'वाड़ी' कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :- (क) बागवानी विकास (फल/औषधीय फसल एवं वानिकी पौधरोपण) मुख्य अवयव हैं, तथा (ख) मृदा संरक्षण, (ग) जल संसाधन प्रबन्धन (संरक्षण एवं उपयोग), (घ) उन्नत कृषि, (ङ) मानव संसाधन विकास (समुदाय विकास), (च) महिला विकास, (छ) सामुदायिक स्वास्थ्य (ज) भूमिहीन लोगों के लिए सूक्ष्म उद्योग विकसित करना।

Nutritional and Economic Security for Tribal & Marginalized Communities (NEST)

To provide nutritional and economic security for tribal and marginalised communities IFFDC has initiated projects with financial assistance from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) for the development of Small Orchard/Wadi. The project addresses the growing concerns related to malnutrition in women and children in rural areas and the need to look at these problems in a wider perspective to find appropriate integrated solutions. These projects envisage the mobilisation and organising of tribal families into affinity based groups called 'Wadi Tolee' and building their capacity to grow fruit trees, alongwith inter-cropping and other allied activities, on designated pieces of land. The emphasis is on up-scaling beyond family consumption to build a value chain that will serve to enhance income and livelihoods. The project has diverse ramifications for integrated rural development from supplementing incomes to increasing land productivity.

PROGRESS

The Wadi programme is being implemented with the financial support of NABARD. The major components of the Wadi Programme include: (a) Orchard development (fruit/plantation/herbal crops & forest plants) as the core component (b) Soil conservation (c) Water resources management (conservation and use) (d) Improved agriculture (e) Human Resource Development (Community Development) (f) Gender Mainstreaming, (g) Community Health (h) Micro-enterprises Development for landless people.

परियोजना विवरण

राज्य	जिला	लक्षित परिवार	लाभान्वित परिवार
मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा	2,000	1,840
राजस्थान	प्रतापगढ	2,750	1,877
छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	2,000	2,000
पश्चिमी बंगाल	बांकुरा	500	500
आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद	500	297
झारखंड	पलामू	500	500
	योग	**8,250**	**7,014**

वर्ष के दौरान

- *838 वाड़ी विकसित की गयी जिसमें 55,440 आम, आँवला, काजू के पौधे तथा 87,790 वानिकी पौधे सुरक्षा की दृष्टि से किनारों पर रोपित किए गये।*
- *234 हेक्ट. क्षेत्रफल पर मृदा एवं जल संरक्षण की गतिविधियाँ जैसे खेत की मेड़बंदी, लगातार समोच्चरेखा खाई, स्टेगर्ड ट्रेन्च आदि पूर्ण की गयीं।*
- *899 वाड़ियों के लिए जल संसाधन विकसित किये गये।*
- *114 हेक्ट. क्षेत्रफल पर अन्तःफसल ली गयी।*
- *उच्च गुणवत्ता कम्पोस्ट हेतु किसानों के खेतों पर 78 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयाँ विकसित की गयी।*
- *विभिन्न पहलुओं पर 84 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।*
- *श्रम में कमी और कार्य दक्षता में वृद्धि हेतु 45 निर्धूम चूल्हे, 344 छत की टाइल उपलब्ध करवाये गये।*

प्रारम्भ से अब तक

- *7,014 वाड़ियों में 2,21,180 आम, आंवले तथा काजू के पौधे एवं 14,62,375 वानिकी पौधे खेतों के चारों ओर सुरक्षा हेतु लगाये गये हैं। जिनकी 60 प्रतिशत जीवितता है।*
- *1,572 हेक्ट. क्षेत्रफल पर मृदा एवं जल संरक्षण की गतिविधियाँ जैसे खेत की मेड़बंदी, लगातार समोच्चरेखा खाई, स्टेगर्ड ट्रेन्च आदि पूर्ण की गयीं।*
- *1,110 किसानों को सब्जी की अन्तःफसल लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिण्डी, धनियां, पत्तागोभी, फूलगोभी, मटर, कद्दू, आदि के उच्च उत्पादन प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराये गये।*
- *श्रम में कमी और कार्य दक्षता में वृद्धि हेतु 1,510 निर्धूम चूल्हे, 4,777 छत की टाइल, कृषकों को 3,090 उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाये गये।*

परिणाम

- परियोजना क्षेत्र के गांवों में फलदार वृक्षारोपण से भविष्य में निरन्तर आधार पर अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अवसर पैदा हुए हैं।
- किसानों को उन्नत कृषि गतिविधियों के अपनाने के कारण सब्जी उत्पादन से अच्छी पैदावार और अधिक आय प्राप्त हो रही है।
- जल संसाधन विकास गतिविधियों के कारण सब्जी के क्षेत्रफल और अन्तःवर्ती फसल उगाने के अवसर प्राप्त हुए हैं।
- उच्च गुणवत्ता के उद्यान विकसित होने से किसान स्वयं को मालिक मानकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एवं उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ गयी है।
- श्रम में कमी लाने के लिए की गयीं गतिविधियाँ जैसे धूँम्ररहित चूल्हे और छतों की उन्नत टाइलों से विशेष रूप से परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और रहन-सहन में सुधार हुआ है।

PROJECT DETAILS

State	District	Target Families	Families Covered
Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara,	2,000	1,840
Rajasthan	Pratapgarh	2,750	1,877
Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	2,000	2,000
West Bengal	Bankura	500	500
Andhra Pradesh	Adilabad	500	297
Jharkhand	Palamu	500	500
	Total	**8,250**	**7,014**

During the year

- *838 Wadis were developed by planting 55,440 saplings of Mango, Aonla and Cashewnut and 87,790 forestry saplings planted on the periphery as protection measures.*
- *Soil & Water Conservation measures like Farm bunding, Continuous Contour Trench and Staggered Trench etc have also been completed on 234 ha.*
- *Water resources have been developed for 899 Wadis.*
- *114 ha. area has been brought under intercropping.*
- *78 Vermi Compost units have been developed on farmers fields producing quality compost.*
- *84 training programmes on different issues have been organised.*
- *For drudgery reduction and increasing work efficiency, improved agriculture implements & equipments like 45 smokeless chulhas, 344 glass roof tiles were provided to the farmers.*

Since Inception

- *7,014 Wadis having 2,21,180 plants of Mango, Aonla and Cashewnut were developed and 14,62,375 forestry plants with survival rate of 60% were planted on the boundaries as protection measures.*
- *Soil & Water Conservation measures like Farm bunding, Continuous Contour Trench and Staggered Trench etc have also been completed on 1,572 ha.*
- *1,110 farmers were encouraged to take up vegetable cultivation as intercropping in wadis by providing High Yielding Variety seeds of Chilly, Tomato, Brinjal, Bhindi& Cucurbits etc.*
- *For drudgery reduction, 1,510 smokeless chulhas, 4,777 Glass roof tiles, 3,090 improved Agriculture implements were provided to the farmers.*

Outcome

- Horticulture plantation in the project villages has created opportunities for additional income in the future on sustainable basis.
- Improved Agronomic practices adopted by the farmers has resulted in better crop production and better income from vegetable production.
- Water Resource Development activities provided opportunities to cultivate additional crop of vegetables as intercropping.
- Farmers are proud at becoming owners of established good quality orchards, which has also increased the value of their field.
- Drudgery reducing activities such as, smokeless chulhas, and improved roof tiles resulted in better health and improved lifestyle of the family, particularly women.

समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास

देश में विकास के कार्यक्रमों का मुख्य ध्येय समावेशी विकास होने के उपरान्त भी भूमि, जल, उन्नत आदानो, तकनीकियों एवं सूक्ष्मवित्त जैसे उत्पादक आदानो तक सीमित पँहुच, के साथ-साथ सूखा के प्रति अति संवेदनशीलता एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण गरीबी है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण में, लोगो को केन्द्र बिन्दु में रखा जाता है तथा उनके लिए सम्पत्तियाँ, दक्षता, सहायक नीतियाँ, सशक्त संस्थाओं एवं विनियामक संरचनाओं कउे निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जिससे, विकास को बढावा मिलता है तथा अतिसंवेदनशील समुदाय को सुरक्षा प्राप्त होती है। ताकि, पुरुष एवं महिलाऐं साथ-साथ रोजगार एवं आय अर्जन के नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सकें।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा, इफको एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर सीमांत समुदाय की आजीविका विकास के लिए उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी, मूल्य वृद्धि, विपणन सहायता आदि विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं।

सब्जी उत्पादन पर आयोजित प्रदर्शन से उत्पादित सब्जी

INTEGRATED RURAL LIVELIHOOD DEVELOPMENT

Despite initiatives aimed at inclusive growth in the country, poverty persists because of limited access to productive resources, such as land, water, improved inputs, technology and microfinance, as well as vulnerability to drought and other natural disasters.

IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills, supportive policies, robust institutions and regulatory structures that both encourage growth and protect the most vulnerable, so that women and men together can access new opportunities for income generation and employment.

PROGRESS

IFFDC is taking several measures in collaboration with IFFCO for increasing productivity, reducing costs, value addition, marketing support etc for enhancing livelihood of the marginalised community.

A view of farm pond constructed under IRDP, West Bengal

परियोजना विवरण

परियोजना	राज्य	जिला	लाभान्वित परिवार
एल.आई.आई.आर.डी.	उड़ीसा	पुरी, नयागढ़, केन्द्रपाडा, गंजाम, जगतसिंहपुर, कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर, रायगढ़ा, नूआपाड़ा एवं बौध	18,797
आर.एल.डी.पी.	पश्चिमी बंगाल	हुगली, बांकुरा, पुरुलिया, साउथ 24 परगना	2,054
आई.आर.डी.पी.	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	12,500
आई.आर.डी.पी.	तमिलनाडु	शिवगंगई, पुदुकोट्टई	3,000
एस.आर.पी.ई.पी.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	25,000

उपरोक्तानुसार, 5 परियोजनायें इफको के वित्तीय सहयोग से उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 168 ग्रामों में संचालित की जा रही है।

कृषि विकास पद्धति, जल संसाधन विकास आदि के उपलब्ध उपयुक्त तकनीकियाँ जो कि अभी तक किसानों तक नहीं पहुँची। इस संदर्भ में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आर्थिक स्तर एवं प्रदर्शन प्रभावों के लिए 'किसानों को केन्द्रित' रखते हुए प्रशिक्षण, प्रसार एवं क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाया है।

वर्ष के दौरान

- *40 तालाबों का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार (39 तमिलनाडु, 1 उड़ीसा), 4 ट्यूवेल उड़ीसा में स्थापित किये गये।*
- *60,000 फलदार पौधे जैसे आम, नींबू, अमरूद और आंवला परियोजना गांवों में प्रदान किये गये हैं, जिन्हें किसान आई.एफ.एफ.डी.सी. के तकनीकी मार्गदर्शन में प्रबन्धित कर रहे हैं। 1.00 लाख उच्च गुणवत्तायुक्त यूकेलिप्टस क्लोन, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बिल्ट) से लेकर उड़ीसा में किसानों के 40 हैक्टेयर क्षेत्र में लगाये गये हैं।*
- *37 स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता शिविर तथा 41 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।*
- *234 वर्मी-कम्पोस्ट/कम्पोस्ट एवं पी.एस.एन. कम्पोस्ट गड्ढे बनाये गये हैं।*
- *1,683 किसान उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान जैसे बीज, खाद आदि से लाभान्वित हुए हैं।*

प्रारम्भ से अब तक की प्रगति

- *जल संसाधन विकास के लिए 367 तालाबों का गहरीकरण, 5 कुओं का निर्माण, 89 चेकडेम और 107 ट्यूवैल विकसित किये गये हैं। इसी प्रकार पीने के स्वच्छ पानी की सुनिश्चितता हेतु 61 हेंडपंपों की स्थापना की गयी है।*
- *2,079 किसानों को 4,370 मीटर सिंचाई पाईप एवं 5 टपक सिंचाई प्रणाली प्रदान कर लाभान्वित किया गया है जिससे सिंचाई जल में होने वाली हानि में कमी हुई है।*
- *परियोजना ग्राम के किसानों को उन्नत तकनीकी को अपनाने से अधिक उत्पादन लेने हेतु प्रेरित किया गया। सन्तुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 8,045 मृदा नमूने लेकर उनका परीक्षण किया गया है। किसानों को परीक्षण के आधार पर उर्वरक उपयोग की सलाह दी गयी है। आई.एफ.एफ.डी.सी. की तकनीकी सलाह से 1,249 कम्पोस्ट/वर्मी-कम्पोस्ट पिट तैयार कराये गये।*
- *21,320 किसानों को सब्जी, धान, सरसों, मक्का, मूँग, चना, सूरजमुखी, आलू एवं मूँगफली के उच्च उत्पादक किस्मों के बीज प्रयोग करने हुए प्रोत्साहित किया गया जिनसे फसलों की उपज में बढ़ोत्तरी हुई।*

PROJECT DETAILS

Project	State	District	Families Covered
IRDP	Odisha	Puri, Nayagarh, Kendrapada, Ganjam, Jagatsinghpur, Kalahandi, Koraput, Bolangir, Rayagada, Nuapada and Boudh	18,797
RLDP	West Bengal	Hooghly, Bankura, Purulia, South 24 Parganas	2,054
IRDP	Tamil Nadu	Sivagangai, Pudukottai	12,500
IRDP	Uttarakhand	Haridwar	3,000
SRPEP	Uttar Pradesh	Unnao	25,000

Five projects are being implemented in 168 villages of Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Maharashtra with the financial support of IFFCO.

The focus is on promotion of available appropriate technologies for farming system development, water resource development etc. that have not yet percolated to the farmers' fields. In this regard, the IFFDC is adopting 'Farmer-Centric' processes through training, extension, exposure visits and cluster approach to achieve economies of scale and for having a demonstrative effect.

During the year

- *Deepening and renovation of 40 Ponds (39 in Tamilnadu, 1 in Odisha), installation of 4 tube wells in Odisha have been completed.*
- *60,000 fruit plants viz Mango, Lime, Guava and Aonla have been planted in the project villages and are being maintained by the farmers under the technical guidance of the IFFDC. 40 ha farmers field has been brought under plantation by planting 1.00 lakh high quality Eucalyptus clones mobilized from Ballarpur Industries Ltd. (BILT) in Odisha.*
- *37 Health & Nutritional awareness camps and 41 Veterinary camps were organised.*
- *234 Vermi-compost/Compost/PSN Compost pits have been established.*
- *1,683 farmers have been benefited by providing high quality agri-input like seed, fertilisers etc.*

Since Inception

- *367 Ponds Deepened, 5 Wells & 89 Check Dams constructed and 107 Tube Wells have been established for Water Resource Development. Similarly, for ensuring safe drinking water, installation of 61 hand pumps have been undertaken.*
- *2,079 farmers were benefitted by providing 4,370 meter irrigation pipes and 5 drip irrigation systems, which considerably reduced loss of irrigation water.*
- *Farmers of the project villages are being motivated and facilitated to adopt improved technologies of crop production to obtain higher yields. 8,045 soil samples were tested and the concerned farmers were provided with the results, alongwith recommendations to promote balanced fertilizer application. 1,249 compost/ vermi compost pits have been prepared by farmers under the technical guidance of IFFDC and IFFCO.*
- *21,320 farmers have been encouraged to adopt High Yielding Varieties seeds of Vegetables, Paddy, Mustard, Maize, Moong, Gram, Sunflower, Potato and Groundnut which enhanced the crop yield.*

- *मौजूदा पशुधन से अधिक उत्पादन हेतु समुदाय को पशु पालन और पशुओं की नस्ल सुधार की वैज्ञानिक पद्धतियों से जागरूक किया गया। 574 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।*
- *ओडीशा में, 2.10 लाख उच्च गुणवत्तायुक्त यूकेलिप्टस क्लोन 84 हैक्टेयर क्षेत्र में लगाये गये हैं।*

परिणाम

- कुँओं और ट्यूबवैल के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण अब किसान 2 से 4 बार अपनी फसलों को सिंचित करने लगे हैं। अदरक, मटर, आलू, लहसुन एवं गन्ने आदि नयी फसलों का परियोजना क्षेत्र में प्रचलन हुआ है।
- क्षेत्र के किसानों को अब सुनिश्चित जल संसाधनों के कारण जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध हुई है जिसके माध्यम से वे अपनी पहली फसल को बचा रहे हैं। इन तालाबों के द्वारा पास के कुँओं के पुनर्भरण में भी सहायता मिली है जिसके परिणामस्वरूप दो फसलें ली जा रही हैं।
- हैण्डपंपों की स्थापना/मरम्मत के कारण समुदायों को उनकी बस्ती के पास कठिन समय में पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है।
- मृदा विशेष रूप से क्षारीय मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि देखी गयी है।
- सभी परियोजना गांवों में संस्थागत रूप देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तत्काल जरूरतों और लघु उद्यमों की स्थापना के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान हो रही है।
- विभिन्न आयजनित गतिविधियों और लघु-उद्यमों के माध्यम से आय में वृद्धि हुई है जिससे सदस्यों की आत्म निर्भरता में बढ़ोत्तरी हो रही है।
- जागरूकता कार्यक्रमों के कारण, सामाजिक बुराइयों को कम करने और आजीविका में सुधार करने में समुदाय को मदद हो रही है।
- तमिलनाडु में पिछले 25 से 30 साल से बेकार पड़ी भूमि पर अब धान, मक्का, मूँगफली, गन्ना, केला आदि की अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जा रही है।
- किसान उच्च पैदावार देने वाली किस्मों और नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं जिससे किसानों को अधिक उत्पादन और आय के कारण उनकी आजीविका बेहतर हो रही है।

सब्जी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मिर्च उत्पादन (ओडीशा)

- *The community has been made aware of scientific methodology of Animal Husbandry and Animal Breed Improvement to get more production from the existing cattle. Also, 574 veterinary camps were organized.*
- *84 ha. area has been brought under plantation by planting 2.10 lakh high quality Eucalyptus clones in Odisha.*

Outcome

- Due to increase in water availability in the nearby wells and tube wells, farmers are now able to provide 2-4 times more irrigations to their crops. New crops i.e. Ginger, Peas, Potato, Garlic and Sugarcane have been introduced in the project area.
- Farmers have assured water resource through farm ponds which can save their first crop through life saving irrigation. These ponds have also helped in recharging the nearby wells which resulted cultivation of second crop.
- Safe drinking water has been made available during scarcity periods to the community near their hamlets due to installation/repair of hand pumps.
- Improvement in the soil health particularly alkaline soils led to increase crop productivity.
- All the project villages are institutionalized through Self Help Groups (SHG) by providing financial support for addressing immediate needs and setting up of Micro-enterprises
- Enhanced income of members through various Income Generation activities and Micro-enterprises is leading towards their self-reliance.
- Awareness generation has helped in minimising social evils and improving livelihoods of the community.
- In Tamil Nadu, land lying fallow for last 25 to 30 years has been brought under cultivation of high yielding varieties of crops like paddy, maize, groundnut, sugarcane, banana, etc.
- Farmers have started cultivating High Yield Varieties (HYV) and cash crops for more production and income leading to better livelihoods.

Women & Child Health awareness camp (West Bengal)

सार्वभौमिक अवधान

ऐसे अवधान एवं गतिविधियाँ जो आई.एफ.एफ.डी.सी. की अधिकांश परियोजनाओं कें अन्तर्गत संचालित की जा रही है उन्हें ''सार्वभौमिक अवधानों'' के तहत् रखा गया है, जो निम्नानुसार है :-

अ. सामुदायिक संस्थाएं

सार्वजनिक संम्पत्ति संसाधनों (सी.पी.आर.) के सफलतापूर्वक प्रबन्धन एवं परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के उपरान्त भी, विकास की प्रक्रिया को जारी रखने हेतु, स्थायी तन्त्र विकसित करने के क्रम में सामूहिक कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी विकासात्मक गतिविधियों को संस्थागत रूप देने हेतु सामुदायिक संस्थाओं के संर्वद्धन की नीति को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया है। विकसित किये गये अभिनव समूह सहकारिता की अवधारणा पर आधारित हैं। परन्तु, इनका नामकरण उस प्रयोजन पर निर्भर करता है, जिसके लिए उन्हे विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत गठित किया गया है। इस प्रकार की सामुदायिक संस्थाऐं जैसे कि, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), कृषक क्लब, वाड़ी समूह, जल उपयोग संगठन (डब्ल्यू.यू.ए.) आदि हैं।

उ.प्र. राज्य की वानिकी समिति अध्यक्षों का गुजरात राज्य में शैक्षणिक भ्रमण

CROSS CUTTING INTERVENTIONS

Interventions and activities which are common to most of the IFFDC projects have been placed under the thematic area "Cross Cutting Interventions" which are as under: -

A. Community Institutions

Building capacity for collective action is crucial for the successful management of Common Property Resources (CPR) and to provide sustainable mechanisms for continuing the development process after withdrawal of project based interventions. IFFDC has consciously adopted the policy of promoting Community Institutions for institutionalizing its development interventions. The promoted groups are strongly rooted in the cooperative principles but differently named depending on the purpose for which formed, under its different projects viz: Primary Farm Forestry Cooperatives Societies (PFFCS), Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS), Farmer Producers Organisation (FPO), Farmer Clubs, Wadi Groups, Water Users Associations (WUA) and so on.

PLDCS and SHG members sharing their expriences with Doordarshan team

प्रगति

सामुदायिक संस्थायें

आई.एफ.एफ.डी.सी. स्वयं एक सहकारी संस्था होने के नाते सहकारिता की ताकत से भलीभाँति परिचित है जो स्थानीय स्तर की संस्थाओं को बनाये रखने, उनका विकास करने में तथा परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के पश्चात् भी विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक संस्थाएं, समुदाय की उनके वातावरण में आजीविका को सुनिश्चित करने एवं संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र एवं अवसर प्रदान करती है।

विभिन्न परियोजनाओं के तहत विकसित एवं पोषित सामुदायिक संस्थायें

क्र.सं.	सामुदायिक संस्थायें	कुल संख्या	कुल सदस्य
1.	स्वयं सहायता समूह	1,895	21,512
2.	पी.एफ.एफ.सी.एस.	148	28,580
3.	पी.एल.डी.सी.एस./पी.एल.डी.ए.सी.एस.	78	2,500
4.	किसान क्लब	258	2,599
5.	वाडी समूह/टुकड़ी	180	2,475
6.	जल उपभोक्ता समिति	181	2,124
7.	ग्राम जलग्रहण समिति	61	184
8.	कृषक रुचि समूह	1,970	30,900
9.	कृषक उत्पादक संगठन	29	28,800

प्रारंभ से अब तक

- *1,895 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं पोषण किया गया, जिनमें 21,512 सदस्य है।*
- *148 पी.एफ.एफ.सी.एस. का गठन किया गया, जिनमें 28,580 सदस्य है।*
- *आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आजीविका के अवसर प्रदान करने हेतु 78 पी.एल.डी.सी.एस./पी.एल.डी.ए.सी.एस. का गठन किया गया है जिनकी कुल सदस्यता 2,500 हैं।*
- *कुल 258 किसान क्लब तथा 180 वाड़ी समूहों का गठन किया गया है जिसमें क्रमशः 2,599 तथा 2,475 सदस्य शामिल हैं।*
- *वर्तमान में 181 जल उपभोक्ता समितियाँ तथा 61 लग्रहण समितियाँ कार्यरत हैं, जिसमें क्रमशः 2,124 तथा 184 सदस्य शामिल हैं। ये समितियाँ सामुदायिक सम्पदा संसाधनों पर निर्मित परिसम्पत्तियों, उनकी स्थिरता हेतु अथवा पानी के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करती हैं।*
- *30,900 किसानों को संगठित करते हुए 1,970 कृषक रुचि समूह (एफ.आई.जी.) सबंर्द्धित किये गये हैं। इसी प्रकार, 28,800 कृषक सदस्यों को सम्मिलित करते हुए 29 कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) का संबंर्द्धन किया गया है।*

PROGRESS

Community Institutions

Being a Cooperative itself, IFFDC believes strongly in the strength of 'cooperative action' to uphold institutions at the local level and to provide support to the development process and help them sustain after withdrawal of the project. Community Institutions provide institutional mechanisms and opportunities for collective management of resources.

Community Institutions Development and Nurtured under different Projects

S.No.	Community Institutions	Total No.	Total Members
1.	SHG	1,895	21,512
2.	PFFCS	148	28,580
3.	PLDCS/PLDACS	78	2,500
4.	Farmer Clubs	258	2,599
5.	Wadi Groups/Tukdi	180	2,475
6.	Water User Committee	181	2,124
7.	Village Watershed Committee	61	184
8.	Farmers Interest Groups	1,970	30,900
9.	Farmers Producers Organisation	29	28,800

Since Inception

- *1,895 Self Help Groups have been formed and nurtured, consisting of 21,512 members.*
- *148 PFFCS have been formed for development and management of forests, consisting of 28,580 members.*
- *78 PLDCS/PLDACS were formed in tribal dominated areas to facilitate the delivery of livelihood products having membership base of 2,500.*
- *A total of 258 Farmer Clubs and 180 Wadi Groups with a membership of 2,599 and 2,475 respectively are being promoted.*
- *For management of the assets created on Common Property Resources (CPR), the project facilitates formation of Water User Committees (WUCs) to ensure sustainability of the structures and judicious use of water. So far, there are 181 WUC and 61 Village Watershed Committee (VWC) encompassing 2,124 and 184 members respectively.*
- *1,970 Farmers Interest Groups (FIGs) have been formed by organising 30,900 farmers. Similarly, 29 Farmer Producer Organisations (FPOs) have been promoted by federating FIGs with membership base of 28,800 member farmers.*

ब. जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण

सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत जेंडर को मुख्य धारा से जोडना एवं महिला सशक्तिकरण के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. का दृष्टिकोण विद्यमान गतिविधियों में केवल 'महिला घटक' को जोडना या 'जेंडर समानता घटक' ही नहीं है अपितु महिला भागीदारी को बढ़ाने, उनमें अनुभव, ज्ञान व विकास के मुद्दों पर महिला एवं पुरुषों में रूचि पैदा करने से कहीं अधिक है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से असमान सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाओं को समान एवं महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए उनकी अपनी संरचनाओं के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में किए गये प्रयासों को सभी परियोजनाओं में सार्वभौमिक रूप से 'जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण' के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,206 स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया जा रहा है। जिनकी कुल सदस्यता 17,708 है, जिनमें 92 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। इन समूहों ने अभी तक कुल 292.95 लाख की बचत करके सदस्यों ने आपस में 269.95 लाख का ऋण वितरित किया। स्थानीय बैंक भी इन समूहों को लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनसे सदस्यों की चिरन्तर आजीविका सुनिश्चित हो गयी है। इन समूहों को नियमित बैठक, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषित किया जा रहा है। रु. 200 लाख की राशि से स्थापित चक्रीय कोष ग्रामीण क्षेत्रों में 'सूक्ष्म-वित्त-प्रक्रिया' सहयोग हेतु संचालित किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूहों के अलावा, अन्य सामुदायिक संगठनों जैसे- प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ, प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ, जल उपयोग समितियाँ इत्यादि में भी महिलाओं की सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निम्न गतिविधियाँ ली गयीं।

महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने सम्बन्धी गतिविधियों का विवरण

क्र. सं.	गतिविधियाँ	इकाई	कुल
1	स्वास्थ्य शिक्षा सत्र	सं.	38
2	पीने का स्वच्छ जल	सं.	259
3	धूम्ररहित चूल्हा निर्माण	सं.	35
4	महिला विकास हेतु स्वयं सहायता समूह	सं.	172
5	आय अर्जन गतिविधियाँ	सं.	43
6	महिला श्रम बचत गतिविधियाँ	सं.	344

परिणाम :

- स्वयं सहायता समूह तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर महिलाओं के सामरिक हितों के समाधान से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद कर रहे है।
- स्वयं सहायता समूह, उन्नत कृषि से सम्बन्धित मुद्दों के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं, कार्यात्मक साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक शोषण तथा शराब, जुआ, तम्बाकू आदि की लत जैसी सामाजिक बुराईयों की पहचान कर उनका उपयुक्त समाधान कर रहे हैं।
- लामबंदी से स्वयं सहायता समूह में सम्बंधता, स्वामित्व और समुदाय के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है।
- वर्तमान में सभी परियोजना गांव स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत सहभागी योजना निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।

B. Gender Mainstreaming & Women Empowerment

IFFDC's approach to mainstreaming gender and women empowerment in all its projects is not about adding merely a 'woman's component' or even a 'gender equality component' into an existing activity. It goes beyond increasing women's participation, bringing the experience, knowledge, and interests of women and men to bear on the development agenda. Its efforts for empowering women through transforming unequal social and institutional structures into equal and just structures for both men and women are an essential feature of all IFFDC interventions and constitute the cross cutting thematic area 'Gender Mainstreaming and Women Empowerment'.

PROGRESS

The IFFDC is nurturing 1,206 SHG with a total membership of 17,708 of which 92% are women. The cumulative savings of these groups has reached a staggering Rs.292.95 lakh. Loans taken by members are around Rs. 269.10 lakh. The local banks are also providing financial assistance to them for initiating micro-enterprises for sustainable livelihood development. These SHG are being nurtured through Regular Meetings, Skill Development and Capacity Building Programmes. Furthermore, the revolving fund amounting to Rs. 200 lakh has been operationalised for facilitating Micro-Credit Mechanism in the rural areas.

Apart from Self Help Group formation, women membership is also encouraged in Community Based Organisations such as PFFCS, PLDCS, WUA, etc. During the year following activities were undertaken for Gender mainstreaming.

Details of Gender mainstreaming related activities

S. No.	Activities	Unit	Total
1	Health Education Session	No.	38
2	Safe Drinking Water	No.	259
3	Construcion of Smokeless Chulas	No.	35
4	SHG for Women Development	No.	172
5	Income Generation Activities	No.	43
6	Women Drudgery Reduction Activities	No.	344

Outcome:

- Self Help Groups (SHG) are helping in addressing the fulfillment of immediate needs as well as_the strategic interests of women and helping to bring them into the mainstream.
- In addition to issues related to improved farming, SHG are also discussing their problems related to health, functional literacy, education of children, social exploitation and social evils like addiction to alcohol, gambling, tobacco consumption etc. and are identifying suitable solutions for their problems.
- Mobilization of SHG has created a sense of cohesiveness, ownership and belonging among communities.
- SHG have been institutionalized in all project villages at present, which is ensuring that the women and marginalized communities are actively involved in the participatory planning and implementation exercises.

स. क्षमता निर्माण

आई.एफ.एफ.डी.सी. में क्षमता निर्माण एक सार्वभौमिक अवधान के रूप में आवश्यक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। जिससे, संस्था के कर्मियों/भागीदारों के प्रायोगिक ज्ञान, दक्षता एवं मनोभावों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने प्रशिक्षणों में, निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन अथवा प्रशिक्षण प्रणाली दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण में धारणा प्रणाली के प्रयोग से अनवरत परिवर्तित हो रहे वातावरण में प्रयोग की जा सकने वाली आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सामग्रियों का नियमित विकास सुनिश्चित हो जाता है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने स्थानीय लोगों को परिवर्तनकारी भूमिकाओं के संवारने पर जोर दिया- वह भूमिकाएँ जिनका उद्देश्य व्यक्तियों एवं समूहों की क्षमता निर्माण है। इन भूमिकाओं में स्वयं सहायता समूह एवं अन्य समूहों का निर्माण ग्राम स्तर पर स्थानीय सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण शामिल है। सभी क्षेत्रीय टीमों ने अपने स्तर पर इनकी क्षमता निर्माण अथवा उन्हें गतिविधि में संलग्न करने हेतु कड़े प्रयास किए। वर्ष के दौरान स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 84 प्रशिक्षण, समिति सदस्यों के लिए 7 प्रशिक्षण/एक्सपोजर भ्रमण, जल ग्रहण प्रबंधन पर 27 प्रशिक्षण, बागवानी वृक्षारोपण पर 32 प्रशिक्षण तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर 21 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

परिणाम

- स्वास्थ्य (पशु चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य) एवं जागरूकता के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।
- समुदाय में स्वामित्व की भावना पैदा हुई जिससे अवधानों के पूर्ण स्थायित्व में मदद मिली।
- एक हजार से अधिक स्थानीय स्तर के सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित कर पैरा-प्रोफेशनल जैसे कृषक मित्र, जानकार, स्वयं सेवक, समूह-प्रेरक, इत्यादि का कौशल निर्माण किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा आय अर्जन हेतु गतिविधि

C. Capacity Building

Capacity building, essentially an organised process of providing systematic inputs to personnel/ stakeholders that results in acquisition of practical knowledge, skills and attitudes, is another cross cutting component that IFFDC places great emphasis on.

IFFDC's use of System Approach to Training ensures that training programs and the required support materials are developed continuously to adapt to the variety of needs and rapidly changing environment.

PROGRESS

The IFFDC has laid emphasis on grooming people from the community for performing transformational roles that aim at capacity building of groups and individuals. These roles include promotion of SHGs and other groups and training of village level local service providers. All the teams took initiatives to engage and groom such people. During the year 84 trainings for SHG Members, 7 Training/Exposure Tours for PFFCS members, 27 Trainings on Watershed Management, 32 Trainings on Management of Horticulture plantations, 21 Trainings on different social issues were organised.

Outcomes

- Capacity building programmes have played a crucial role in the field of health (veterinary & human health) and awareness.
- Helped in inculcating a sense of ownership in the community that helps in turn in the overall sustainability of interventions.
- A cadre of more than 1,000 local-level service providers are trained and groomed as para-professionals such as krishakmitras, jankars, volunteers, group motivators, etc, and are involved in skill up-gradation of the community.
- Involvement of women in the training programmes has helped in instilling a sense of confidence in these women.

Design development training for artisans in progress

परामर्श कार्यक्रम

ग्रामीण विकास की, पहले से ही परीक्षित रणनीतियाँ, दृष्टिकोंण, प्रक्रियाऐं, विधियाँ एवं तकनीकियाँ, ग्रामीण विकास के अवधानों के प्रसार, पुनरावृत्ति एवं यथानिर्मित क्रियान्वयन में सहायता करती है। बहुत सारी एजेन्सियाँ हैं जो कुछ अलग करना चाहती हैं । परन्तु उनके पास उसके लिए आवश्यक क्षमता एवं दक्षता नहीं होती है। अतः यह कार्य किसी अन्य संस्था को परामर्श के आधार पर सौंप दिया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने ''परामर्श कार्यक्रम'' के तहत् ऐसी संस्थाओं को उनके प्रतिबद्धताओं को नये तरीके से पूरा करने के लिए सहायता करने का कार्य प्रारम्भ किया है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने कृषि विकास, समुदाय गतिशीलता, संस्थागत विकास, तथा अनुश्रवण एवं प्रभाव आंकलन क्षेत्रों में गहन अनुभव हासिल किया है। कर्मचारियों की व्यावसायिक योग्यता को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी.अन्य एजेंन्सियों के साथ विशिष्ट मुद्दों के रुप में कुछ परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। कुछ परियोजनाओं में कुछ मुद्दों विशेष या आंशिक रूप से संपादन का कार्य भी किया जा रहा है। उक्त प्रकार की परियोजनाओं को परामर्श कार्यक्रम में स्थान दिया गया है।

प्रगति

वृक्षारोपण एवं रखरखाव (भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित)

भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड (बीओआरएल) द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. को वीना रिफाइनरी के चारों ओर हरित पट्टी के अन्तर्गत पौधारोपण एवं रखरखाव करने का दायित्व सौपा गया है।

वर्ष के दौरान हरित पट्टी में 2.34 लाख पौधों की निराई गुडाई, थाला निर्माण, सिंचाई एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से प्रबंधन किया जा रहा है। इसी प्रकार 35,000 नए पौधों का रोपण एवं प्रबंधन भी आई.एफ.एफ.डी.सी. के तकनीकी मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करना (एमपावर)

पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को कम करना (एमपावर) परियोजना इफाड के सहयोग से राजस्थान सरकार द्वारा शुरु की गई एक पहल है। पश्चिमी राजस्थान में गाँव स्तर पर विभिन्न आजीविका गतिविधियों के सहयोग एवं सेवा तंत्र की स्थापना के लिए सामुदायिक संस्थाओं के विकास के माध्यम से गरीबी को कम करने के उद्देश्य से परियोजना का निर्माण किया गया है।

वर्ष के दौरान, 86 स्वंय सहायता समूहों का गठन एवं 18 ग्राम विकास समितियों की स्थापना की गई जिनमें 39 समूहों के बैंक में खाते खुलवाए गए। सदस्यों की क्षमता विकास हेतु विभिन्न मुद्दों पर 41 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन एवं दलहन उत्पादन कार्यक्रम

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के द्वारा 5 राज्यों में राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन एवं दलहन कार्यक्रम के तहत कृषक उत्पादक संघठन (एफपीओ) के गठन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को पार्टनर संस्था के रुप में चयनित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाजार में सब्जी एवं दलहन की अतिरिक्त आवक एवं उत्पादन में बढोतरी करना है।

CONSULTANCY PROGRAMME

Already tested strategies, approaches, processes, methodologies and technologies of rural development are helpful in dissemination, replication and tailor-made implementation of rural development initiatives. Many agencies, desirous of making a difference, do not possess the requisite capacity or skills for doing so and assign specific tasks on consultancy basis. IFFDC has started facilitating such agencies in achieving their commitments in innovative ways under its "Consultancy Programme".

IFFDC has gained experience in the field of Farm Forestry Development, Agriculture Development, Community Mobilisation, Institution Development, Monitoring and Impact Assessment. Professional skills of its staff members have been recognised by other institutions, Government and other agencies. The IFFDC is implementing some projects in association with the other agencies as a service provider for specific tasks or jobs. In some projects, it has been assigned a part of the work or specific component of the whole project for implementation. Such projects are included under the head of Consultancy Projects.

PROGRESS

Up-keeping and Maintenance of Plantation (Bharat Oman Refinery Limited Funded)

The IFFDC has been engaged by the Bharat Oman Refinery Limited (BORL) for providing, planting and initial maintenance of Tree Saplings in the Green Belt in the surrounding area of the refinery located in Bina.

During the year, Green Belt consisting of 2.34 lakh trees have been nurtured by undertaking maintenance activities like weeding and hoeing, Basin Making, Irrigation etc. Moreover, 35,000 new saplings have been planted in the Green Belt and are being maintained under the technical guidance of IFFDC.

Mitigating Poverty in Western Rajasthan (MPOWER)

Mitigating Poverty in Western Rajasthan (MPOWER) is a poverty reduction initiative that is supported by IFAD. The project is designed to uplift the poor community from the vicious circle of extreme poverty through development of grassroots community institutions and support to various livelihoods activities and initially setting up of services delivery systems .

During the year, 86 new Self Help Groups and 18 Village Development Committees (VDC) have been formed and 39 groups have been facilitated for opening bank account. 41 trainings on various aspects have been conducted for building their capacity.

National Vegetable Initiative and Pulse Production Programme

The IFFDC has been engaged by Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC) as an implementing partner for National Vegetable Initiative (NVI) and Pulse Programme for Promotion of Farmers Producer Organisations (FPO) in 5 States. The main objective of the programme is to increase marketing access and enhancement of production.

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन कार्यक्रम का क्रियान्वयन दो राज्यों हरियाणा एवं उत्तराखण्ड में 5,538 किसानों के 311 कृषक रुचि समूहों (एफआईजी) के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष के दौरान उद्यान निदेशालय द्वारा 13 प्रशिक्षण, 10 कार्यशाला, 2 एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन बागवानी विभाग की सहायता से किया गया, जिनमें 1,511 किसानों ने भाग लिया। उद्यान निदेशक, हरियाणा द्वारा सभी परियोजना जिलों में कुल रु. 337 लाख की राशि कृषक रुचि समूहों (एफपीओ) के खातों में जमा की गयी।

दलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में 19,848 किसानों को शामिल करते हुए 1,066 कृषक रुचि समूहों का गठन किया गया है। किसानों को कार्यक्रम की दृष्टि एवं मिशन से अवगत कराने हेतु कृषक रुचि समूहों के 2,114 सदस्यों को 51 प्रशिक्षणें के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। मध्य प्रदेश में 4 कृषक उत्पादक कम्पनियों रजिस्ट्रेशन कराया गया।

कृषि आधारित मूल्य संबर्धन शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) सेवा के लिए 8,810 सब्जी एवं दलहन उत्पादक कृषकों को रेयूटर मार्केट लाइट (आरएमल) से भी जोड़ा गया। ए.एल.सी. लिमिटेड की सहायता से राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन एवं दलहन उत्पादन कार्यक्रम में कार्यरत व्यावसायिक स्टाफ को 'ओवरऑल ओरियन्टेशन ऑन एफपीओ प्रोमोशन', 'स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग', 'रजिस्ट्रेशन एंड लीगल कम्पलाइन्सेस फार प्रमोशन ऑफ एफपीओ' तथा मॉनिटरिंग इनफारमेशन सिस्टम' पर 4 कार्यशालाएं आयोजित की गई ।

राष्ट्रीय स्तर मॉनिटर (एन.एल.एम.)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. को केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु चयनित किया गया है।

हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के 4 जिलों में मॉनिटरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर मॉनिटरिंग के तहत कुल 10 जिलों का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

The NVI programme is being implemented in two states viz. Haryana and Uttarakhand with 311 Farmer Interest Groups (FIGs) covering 5,538 farmers. During the year, 13 Trainings, 10 Workshops, 2 Exposures were organized with the help of Horticulture Department in which, 1511 farmers participated. To promote vegetable cultivation, an incentive of Rs.337 lakh was deposited in the FIG accounts by the Director Horticulture, Haryana covering all the districts under the project area in Haryana.

Under the Pulse Programme in 3 States- Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, 1,066 FIGs have been formed covering 19,848 members. In order to instil in the community, the vision and mission of the programme, 51 trainings were organized for the Farmer Interest Groups (FIG) comprising of 2,114 members. 4 Farmer Producer Companies have been registered in Madhya Pradesh by federating the FIGs.

Also, 8,810 Vegetable and Pulse farmers have been linked with Reuter's Market Light (RML) for agri-based value added short messaging services (SMS). For the professional staff working in both NVI and Pulses Programme, 4 workshops have been conducted on- 'Overall Orientation on FPO Promotion', 'Strategic and Business Planning', 'Registration and Legal Compliance for Promotion of FPOs' and 'Monitoring Information System' supported by ALC Ltd.

National Level Monitors (NLM) :

IFFDC has been identified by the Minisry of Rural Development, Govt. of India to monitor centraly sponsored schemes.

Monitoring work were completed in 4 district of MP and Haryana. Total 10 districts have been covered under NLM Programme nd report have been submitted to Ministry.

बीज एवं कृषि आदानों की आपूर्ति
SEED & AGRI-INPUTS SUPPLY

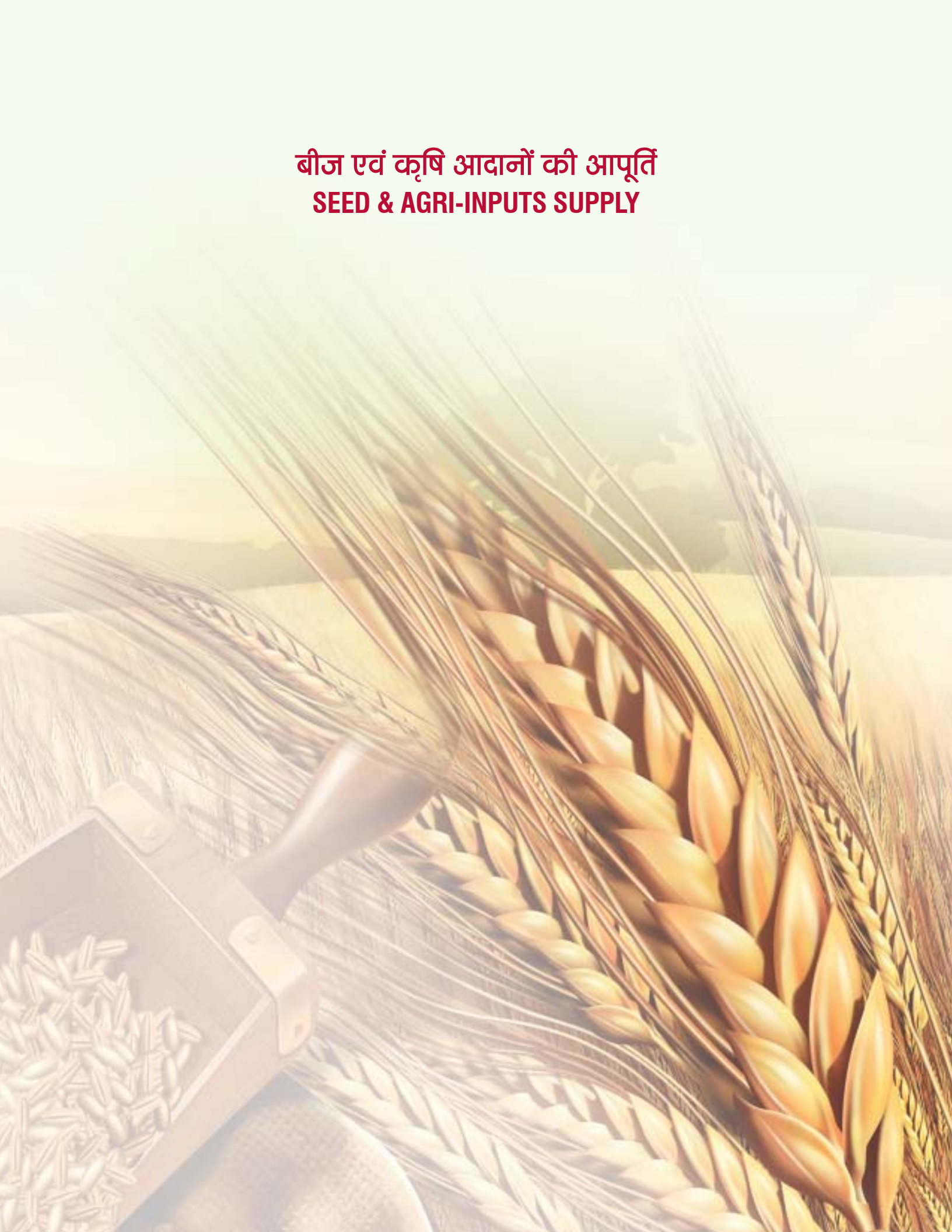

बीज उत्पादन कार्यक्रम

बीज कृषि उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रांतिक आदान है जिस पर अन्य कृषि आदानों की कार्य क्षमता एवं प्रभाव बहुत हद तक निर्भर करता है। भिन्न-भिन्न फसलों में केवल सही बीज के प्रयोग से ही फसल उत्पादन में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है तथा बीज के साथ अन्य कृषि आदानों के बेहतर प्रबंधन से फसल उत्पादन को 45 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि-जलवायु परिस्थतियों में अधिक उत्पादन देने वाले बीज की समुचित मात्रा उचित मूल्य पर उपलब्ध होना आवश्यक है। नई व उन्नतशील किस्मों के बीजों का विकास कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तर बढ़ोत्तरी के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिससे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह साबित हो चुका है कि भविष्य के खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापना दर (सीड रिप्लेसमेंट रेट) को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह कार्य करने के लिए हमें उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हालांकि हमारे देश में अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ रहा है, फिर भी, बढ़ती हुई जनसंख्या व कृषि उत्पादन की गति को देखते हुए इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

हमारे देश में अधिकतर किसानों को आज भी अच्छी गुणवत्ता का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे वे पुरानी किस्मों व अनुपयुक्त बीजों का ही बार-बार उत्पादन कर उसे ही बीज के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं। इससे फसलों का उत्पादन गिर रहा है व देश में खाद्य असुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। देश में खाद्यान्न उत्पादन के न बढ़ने व भोजन उपलब्धता कम होने का एक प्रमुख कारण अच्छी गुणवत्ता के बीजों का समय पर उपलब्ध न होना है।

इस समस्या के समाधान हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसान केन्द्रित बाजारोन्मुखी बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों में आई.एफ.एफ.डी.सी. व राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (एस.एस.सी.ए.) के तकनीकी पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन किया जा रहा है। बीज उत्पादन कार्य में रुचि रखने वाले व आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन के मापदण्डों को पूरा करने वाले किसानों को "बीज उत्पादक समूहों" (एस.जी.जी) के रूप में संगठित कर उनमें उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं के अथवा किराये के प्रसंस्करण संयंत्रों पर अपने पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन के तकनीकी पहलुओं के अनुरूप प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से मानकीकरण करवाने के पश्चात् सहकारी बिक्री तन्त्र के माध्यम से बीज किसानों को विपणन किया जाता है।

SEED PRODUCTION PROGRAMME

Seed is the critical determinant of agricultural production on which depend the performance and efficacy of other inputs. Seed itself can potentially raise total production by about 15 – 20% depending upon the crop and further up to 45% with efficient management of other inputs. Quality seeds appropriate to different agro-climatic conditions and in sufficient quantity at affordable prices are required to raise productivity. Availability and use of quality seeds is not a onetime affair. Sustained increase in agriculture production and productivity necessarily requires continuous development of new and improved varieties of crops befitting to the needs of the farmers and efficient system of production and supply of seeds to farmers.

It has become evident that in order to achieve the food production targets of the future, a major effort will be required to enhance the seed replacement rates of various crops. This would require a major increase in the production of quality seed. Although, the growth of Seed sector in India is remarkable but still there are areas where endeavours required to be made to cop up with the pace of increase in population and agriculture production.

Most of the farmers in the country have little or no access to improved seed and continue to recycle seed that has been exhausted after generation of cultivation. Crop Yields have remained poor, resulting in persistent food insecurity. Lack of timely availability of quality seed is one of the problem for dwindling agriculture productivity and shrinking food availability.

To address this problem, the IFFDC has initiated a 'farmer centric', market driven Seed Production Programme, which is fast becoming a major activity. Seed is being produced on farmer's fields under technical supervision of IFFDC and the State Seed Certification Agencies (SSCA). Interested farmers fulfilling the criteria of "IFFDC Seed Production Guidelines" are organised into "Seed Grower Groups" (SGG) and their capacities are built for seed quality control alongwith technical aspects of seed production. The seed is then processed either in IFFDC's own processing plants or hired processing plants under its supervision as per the "Seed Certification Standards". After certification by the SSCA, the seed is being marketed to the farmers through the existing cooperative network.

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता बढ़ाने व कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बीज उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम किया जा रहा है।

अधिक से अधिक कृषकों को बीज उत्पादन प्रणाली से जोड़ने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 'बीज उत्पादक समूह' के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित हो सके व साथ ही उनमें क्षमता विकास हो व गुणवत्ता पूर्ण बीजो के उत्पादन को बढावा मिले। इन बीज उत्पादकों समूहों को नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों व जागरूकता लाने वाली गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन के लिये आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी स्वयं की आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली विकसित की गई है जिससे तहत विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज स्त्रोंतों का प्रबंधन, बुवाई, खड़ी फसल में की जाने वाली क्रियायें, कटाई उपरान्त गतिविधियाँ, प्रसंस्करण व प्रमाणीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि के समय निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

संपर्क (लिंकेज) विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा तिलहन फसलों के आधार एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय तिलहन एवं पॉम ऑयल मिशन में अपना पंजीकरण करावाया गया है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जनक एवं आधार बीजों के क्रय के लिए भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य बीज निगमों व अन्य सस्थानों के साथ तथा उत्पादित बीज के प्रमाणीकरण के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित किये गये हैं।

आधारभूत/ढ़ांचागत विकास

उच्च गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन एवं किसानों तक बीज पहुँचाने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के महत्पूर्ण स्थानों पर मय बीज प्रसंस्करण की स्थापना संयंत्र की स्थापना एवं इन क्षेत्रों में बीजों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए सुविधायें विकसित की जा रही हैं। पंजाब के रामपुरा फूल में 5 टन प्रति घंटा की क्षमता वाले आधुनिक संयंत्र की स्थापना 25,000 क्विंटल बीज भण्डारण क्षमता के गोदाम के साथ की गयी है। इसके अलावा हरियाणा के हिसार जिले में दुर्जनपुर, व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के चपरतला में कार्य प्रगति पर है। अन्य स्थानों पर क्रय की गई भूमि पर नयी बीज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

वर्ष के दौरान

उत्पादन

- *खरीफ 2013 के दौरान कुल 18,296 क्विंटल बीज (9,328 क्विंटल धान, 7,943 क्विंटल सोयाबीन, 348 क्विंटल मूँग, 500 क्विंटल अरहर एवं 181 क्विंटल ग्वार) का उत्पादन किया गया जो कि, खरीफ 2014 में आपूर्ति के लिये उपलब्ध हो जायेगा।*
- *रबी 2013-14 के दौरान लगभग 3.88 लाख क्विंटल बीज (3.80 लाख क्विंटल गेंहूँ, 4,545 क्विंटल चना, 668 क्विंटल जौ, 640 क्विटल मसूर, 1,545 क्विंटल मटर और 85 क्विंटल सरसों का रॉ बीज उत्पादित किया जा रहा है जो प्रसंस्करण उपरान्त रबी 2014-15 में आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगा।*
- *इसी प्रकार, लगभग 8,440 क्विंटल आधार बीज (8,090 क्विंटल गेहूँ एवं 350 क्विंटल चना) आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्पादित किया गया जो कि अगले वर्ष के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।*

विपणन

- *खरीफ 2013 के दौरान, कुल 9,885 क्विंटल बीज (9,074 क्विंटल धान, 608 क्विंटल सोयाबीन, 32 क्विंटल ग्वार, 171 क्विंटल अरहर एवं 1,100 क्विंटल ढैंचा) की बिक्री किसानों को सहकारिता नेटवर्क के माध्यम से की गई है।*

PROGRESS

IFFDC has undertaken Seed Production and Marketing in the states of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab and Chhattisgarh to increase availability of quality seed and thus enhance agricultural productivity.

To bring farmers under the ambit of the Seed Production System, the IFFDC is focusing on formation of Seed Growers Groups (SGG), which establishes effective communication with the farmers, helps in capacity building and also ensure quality seed production. These SGGs are being nurtured through regular meetings, training and other awareness creating activities. For ensuring the quality of seeds produced, the IFFDC has an inbuilt Internal Quality Control (IQC) System which involves inspection and control at various critical stages viz. arranging seed sources, sowing, field/crop level, post-harvest, processing, certification, packaging, storage, transportation etc. Wider publicity of IFFDC seeds is being undertaken through organising various activities.

Linkages Development

IFFDC has got registered with National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP), Ministry of Agriculture (DAC), Govt of India for Producing and Distributing the Foundation and Certified Seed of oilseedand oil-palm crops.It has developed strong linkages with National Seed Association of India (NSAI), National Seed Corporation (NSC), Agricultural Universities, Research Institutes, State Seed Corporations and other Agencies for procuring Breeder/Foundation Seed and also with the State Seed Certification Agencies for getting Certification of the Seeds produced by it.

Infrastructure Development

For quality seed production and timely supply at the doorsteps of the farmers, the IFFDC is in the process of Setting up new Seed Processing Plants and Scientific storages in the area of operation. It has purchased lands/plots at the strategic locations in the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh.It's first Seed Processing Unit – "The Arch of Excellence" at RampuraPhul, Bhatinda (Punjab) has been developed with 5TPH capacity modern Plantalongwith scientificstorage godownwith a capacity of 25,000 qtlsSeeds. Moreover, the construction work at Durjanpur (Dist. Hisar, Haryana) and Chapartala (Dist. LakhimpurKhiri, Uttar Pradesh) is under progress. The work for setting up new Seed Processing Units will immediately be started on the Plots/land purchased at other places.

During the year

Production

- *During Kharif 2013, total 18,296 qtls seeds (9,328 qtls Paddy, 7,943 qtls Soybean, 348 qtls Moong, 500 qtls Arhar and 181 qtls Cluster bean) have been produced and will be available for supplying during Kharif 2014.*
- *During Rabi 2013-14, approximately 3.88 lakh qtls seeds (3.80 lakh qtls Wheat, 4,545 qtls Gram, 668 qtls Barley, 640 qtls of Lentil, 1,545 qtls Pea, 85 qtls Mustard raw seeds) is being produced after processing, the same will be available for supplying during Rabi 2014-15.*
- *Similarly, approximately 8,440 qtls Foundation Seed (8,090 qtls Wheat and 350 qtls Gram) raw seeds have been produced by IFFDC for further multiplication.*

Marketing

- *During Kharif 2013, total 9,885 qtls seeds (9,074 qtls Paddy, 608 qtls Soybean, 32 qtls Guar, 171 qtls Arharand 1100 qtls Dhaincha) has been sold to the farmers through cooperative network.*

- *रबी 2013-14 के दौरान कुल 2,17,107 क्विंटल (2,09,914 क्विंटल गेहूँ, 4,743 क्विंटल चना, 1,700 क्विंटल मटर, 450 क्विंटल मसूर तथा 300 क्विंटल सरसों) बीज को सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को आपूर्ति किया गया है।*
- *वर्ष 2013-14 के दौरान, बीज उत्पादन में पिछले तीन वर्षो से 4-गुना वृद्धि हुई जबकि बीज विपणन में पिछले 2 वर्षों में 3-गुना वृद्धि हुई है।*

बीज उत्पादक समूह (एस.जी.जी.) और बीज प्रचार–प्रसार

- कुल 1200 सदस्यों के साथ 94 बीज उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। मृदा परीक्षण के लिए, 1070 मिट्टी के नमूनों का मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण कराया गया तथा उसके अनुसार, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग सुनिश्चित किया गया। 9,970 किसान प्रतिभागियों के साथ 1095 बीज उत्पादक समूहों की बैठकों का आयोजन भी किया गया।
- बीज उत्पादन एवं बीज गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए 44 प्रशिक्षण आयोजित किए गये, जिनमें 1,200 उत्पादक सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, इन कृषक समूहों के सदस्यों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की नई तकनीकियों की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान संस्थानों में 10 भ्रमणों और कृषि विश्वविद्यालयों के कृषक मेलों में 12 भ्रमणों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, 529 उत्पादक सदस्यों को आई.के.एस.एल. के मूल्यवर्धित संदेश सेवाओं की नियमित जानकारियों से जोड़ा गया जिसके माध्यम से उन्हें फसल एवं बीज उत्पादन की उन्नत तकनीकियों एवं पद्धतियों की जानकारी प्रदान की गयी।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. बीज के प्रचार-प्रसार के लिए, 27 किसान-दिवसों, 9 फसल संगोष्ठी, 13 विशेष बिक्री अभियान, 47 सहकारी सम्मेलन, 377 ट्रैक्टर ट्राली पेंटिंग, 20 किसान मेलों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा विभिन्न स्थानों पर बोर्ड एवं बैनर आदि लगाये गये।

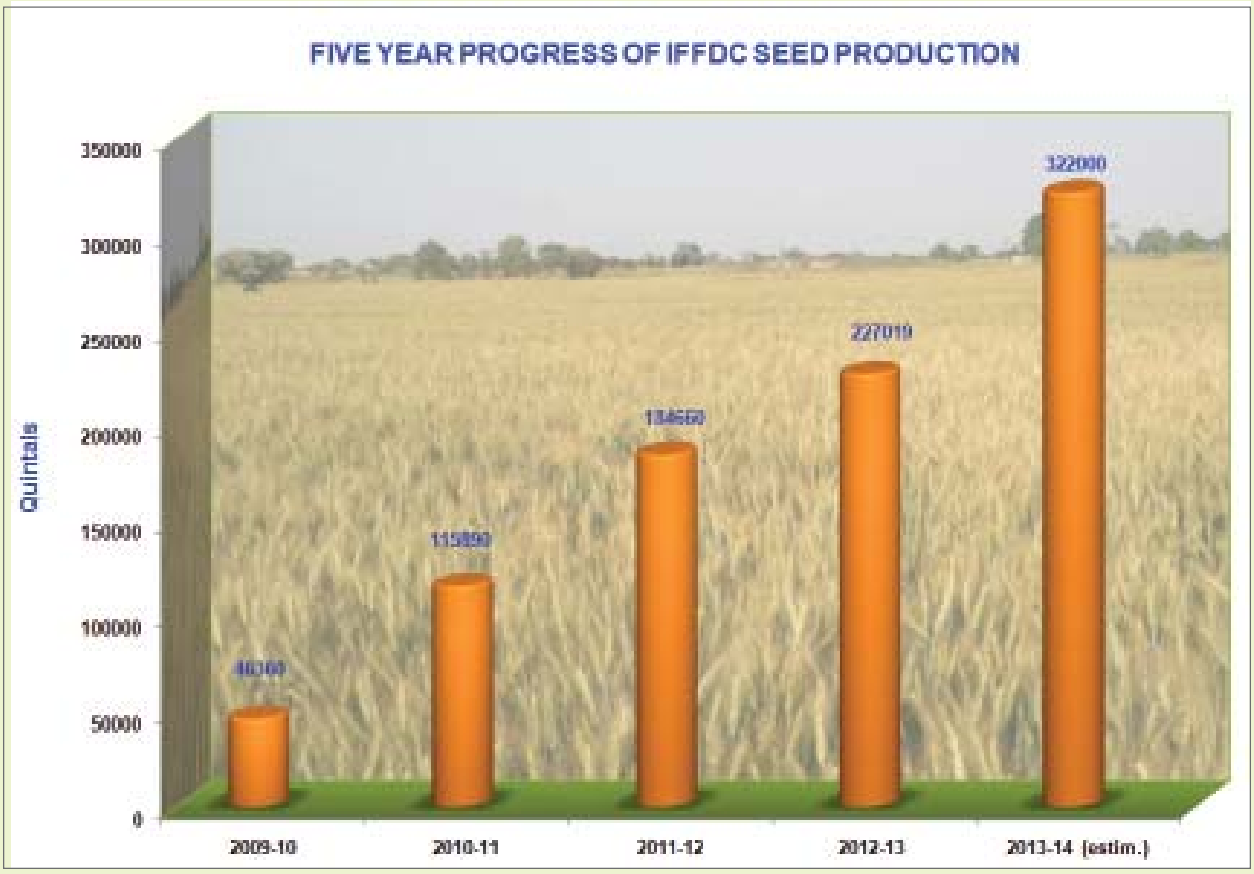

- *During Rabi 2013-14, total 2,17,107 qtls (2,09,914 qtls Wheat, 4,743 qtls Gram,1700 qtls Pea, 450 qtls Lentil and 300 qtls Mustard) seeds have been supplied to the farmers through cooperative network.*
- The growth in seed production during the year 2013-14 over last three years is 4-fold while in case of marketing of certified seed, the business has increased 3-fold over the last two years.

Seed Grower Groups (SGG) and Seed Publicity

- Total 94 Seed Grower Groups with 1200 members have been formed. For soil testing, 1070 soil samples from farmers' fields have been analysed through soil testing laboratories and balanced fertilisers application accordingly ensured. Total 1095 meetings of SGGs with participation of 9970 farmers have also been organized.
- To impart technical inputs on seed production, and seed quality control etc, 44 training programmes have been organised in which 1200 grower members participated. Besides this, 10 exposure visits to the Agriculture Research Institutes and 12 visits to the Farmer Fairs of Agriculture Universities have also been organised to expose them to new technologies and practices of quality seed production. Moreover, 529 member growers have been linked with IKSL's value added messaging services and are benefitted through regular information about need based improved packages and practices of crop/seed production.
- Wider publicity of IFFDC Seed has been undertaken through organising 27 Field-days, 9 Crop Seminars, 13 Special Sales Campaigns, 47 Cooperative Conferences,377 Tractor Trolley Paintings, participating in 20 Exhibition Stalls in Farmers Fairs, displaying boards and banners etc at various places.

कृषि–आदानों की आपूर्ति

स्थाई रूप से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. अपनी वितरण श्रृंखला (कृषि-वानिकी सेवा केन्द्र, पी.एफ.एफ.सी.एस. नेटवर्क, कृषक सेवा केन्द्र आदि) द्वारा दूरदराज किसानों को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

प्रगति

कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में 7 कृषि वानिकी सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के द्वारा वानिकी बीज, उच्च उत्पादन किस्म बीज, इफको उर्वरक और जैव उर्वरकों की आपूर्ति के साथ-साथ कृषि वानिकी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 6,658 मैट्रिक टन इफको खाद (4,768 मैट्रिक टन यूरिया, 123 मैट्रिक टन एन.पी.के, 1,837 मैट्रिक टन डी.ए.पी., 30 मैट्रिक टन फास्फो-जिप्सम) के साथ-साथ 1.5 मैट्रिक टन जैविक उर्वरक, 2,530 क्विं. गेहूँ एवं धान के प्रमाणित बीज की आपूर्ति इन कृषि वानिकी सेवा केन्द्रों द्वारा किसानों को की गयी।

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति तन्त्र

उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इफको उर्वरकों का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान, कुल 21 समितियों ने 8,435 मैट्रिक टन इफकों उर्वरक जिसमें 5,895 मैट्रिक टन यूरिया, 2,258 मैट्रिक टन डी.ए.पी. तथा 282 मैट्रिक टन एन.पी.के. और विभिन्न फसलों के 7,511 क्विं. गुणवत्ता युक्त बीज की आपूर्ति की गयी।

कृषक सेवा केन्द्र (के.एस.के.)

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु एवं पश्चिमी बंगाल राज्य के विषेशकर उन क्षेत्रों/जिलों में जहाँ सहकारी समितियां कमजोर हैं, वहाँ गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषक सेवा केन्द्र खोलकर एक वितरण श्रृंखला प्रणाली विकसित की गई। उत्तर प्रदेश में संचालित इस प्रकार के 1,577 केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 3,65,352 मैट्रिक टन इफको उर्वरक जिसमें 2,74,303 मैट्रिक टन यूरिया, 74,926 मैट्रिक टन डी.ए.पी., 14,371 मैट्रिक टन एन.पी.के. , 40 मैट्रिक टन डब्ल्यू.एस., 1,632 मैट्रिक टन फास्फो-जिप्सम, 80 मैट्रिक टन जैविक उर्वरक तथा गेहूँ व धान के 55,151 क्विं. गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की गई।

AGRI-INPUTS SUPPLY

To increase production and productivity of crops, timely supply of quality agri-inputs to the farmers even in the remote areas is being ensured by IFFDC through its supply chain (Agro-forestry Service Outlets, PFFCS Network, Krishak Seva Kendra etc).

PROGRESS

Agro-Forestry Service Outlets

The IFFDC is operating 7 Agro-Forestry Service outlets (AFSO) in Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, and West Bengal. These AFSO are providing inputs like, forestry seed, HYV seed, IFFCO fertilizers and bio-fertilizers alongwith technical guidance to farmers. During the year, 6658 MT IFFCO fertilizers (4768 MT Urea, 123 MT NPK, 1837 MT DAP, 30 MT of Phospho-zypsum) along with 1.5 MT of Bio-fertilisers, 2530 qtls certified seeds of Wheat and Paddy have been supplied to the farmers through these AFSO.

PFFCS Network

The Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh were encouraged to take up the marketing of fertilizers and other Agri-inputs for economic self-sufficiency. 21 PFFCS have marketed 8435 MT IFFCO fertilizers, comprised of 5,895 MT Urea, 2,258 MT DAP and 282 MT NPK and also 7,511 qtls of quality seeds of various crops.

Krishak Seva Kendra (KSK)

To provide quality agricultural inputs, a delivery chain mechanism has been developed by opening IFFDC Krishak Seva Kendras (KSKs) in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Tamilnadu & West Bengal especially in the areas/ districts where cooperative societies are weak. 1577 such Centers operating in Uttar Pradesh supplied 3,65,352 MT of IFFCO fertilizer i.e. 2,74,303 MT Urea, 74926 MT DAP and 14371 MT NPK, 40 MT WS, 1632 MT Phospho-zypsum, 80 MT Biofertiliser and 55151 qtls of quality seeds of wheat and paddy has been marketed.

Marketing Director, IFFCO and Director, IFFDC visiting IFFDC FSC

मानव संसाधन प्रबंधन

प्रारम्भ से ही आई.एफ.एफ.डी.सी. में प्रोफेशनल को सभी स्तरों पर पर्याप्त अवसर दिया गया है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आई.एफ.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों की कुल संख्या 266 है जिसमें 32 महिला कर्मचारी हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रेरित तथा समर्पित मानव पूँजी के पोषण तथा विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रगतिशील, समग्र और स्थाई दृष्टिकोण को अपनाया है। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने कर्मचारियों की प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए आवश्यकता आधारित विशेष प्रशिक्षणों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया है। वर्ष के दौरान, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से अपने 184 स्टॉफ सदस्यों की क्षमता का निर्माण किया।

1. मई 21-24, 2013 के दौरान, एक चार दिवसीय प्रशिक्षण "बीज कार्यक्रम उन्मुखीकरण" पर आई.एफ.एफ.डी.सी. मुख्यालय, गुड़गांव में 24 सदस्यों ने भाग लिया।
2. एक तीन दिवसीय कार्यशाला "बीज उत्पादन उन्मुखीकरण एवं कम्प्यूटर संचालन" विषय पर मई 21-23, 2013 के दौरान, आई.एफ.एफ.डी.सी. मुख्यालय, गुड़गांव में आयोजित किया गया, जिसमें स्टाफ के 31 सदस्यों ने भाग लिया।
3. मई 24, 2013 को "बीज कार्यक्रम के कम्प्यूटर साफ्टवेयर ई-पवन की समीक्षा" पर एक दिससीय कार्यशाला का आयोजन आई.एफ.एफ.डी.सी. मुख्यालय, गुड़गांव में एक कार्यशाला का आयोजित किया गया जिसमें 16 संभागियों ने भागीदारी की।
4. मई 31 से जून 01, 2013 के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र करनाल में "बीज उत्पादन, प्रसंस्करण एवं सुरक्षित भण्डारण की नवीनतम जानकारी" पर दो दिवसीय एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों के स्टाफ के 24 सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
5. "सोयाबीन के बीज उत्पादन की तकनीकियों" विषय पर सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इन्दौर में जून 18-19, 2013 के दौरान दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से स्टाफ के 10 सदस्यों ने भागीदारी की।
6. जुलाई 10-11, 2013 को इफको-एफ.एम.डी.आई., गुड़गांव में दो दिवसीय एक प्रशिक्षण "क्रय प्रक्रिया, अधिकारियों की शक्तियाँ, लेखा प्रणाली, अंकेक्षण एवं सम्बन्धित अन्य आयाम" पर आयोजि किया गया। जिसमें 42 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।
7. ब्रह्मकुमारी के ओम शान्ती रिट्रिट केन्द्र, मानेसर में "कार्य आचार" पर सितम्बर 3-4, 2013 को दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 37 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।
8. बीज गुणवत्ता नियंत्रण पर एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनवरी 31-फरवरी 01, 2014 को कोटा, राजस्थान में किया गया, जिसमें 34 स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया।
9. फरवरी 03-04, 2014 को एन.सी.डी.सी., टॉपिक संस्थान, गुड़गांव में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "स्वयं सहायता समूह प्रबंधन" विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के 32 सदस्यों ने भागीदारी की।

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Since inception, the IFFDC has been giving generous opportunity to professionals at all levels. Out of its total strength of 266 employees as on 31st March, 2014, there are 32 female employees.

IFFDC has adopted a forward looking, people centric approach for nurturing and developing motivated and committed human capital. IFFDC places major emphasis on capacity building through need-based and specialised training of its staff for effective functioning. During the year, IFFDC build the capacity of its 184 staff members through organizing need based trainings and workshop.

1. A Four-days Training on "Orientation of Seed Programme" with the participation of 24 staff members was organized at IFFDC Head Office, Gurgaon during May 21-24, 2013.

2. A Three-days workshop on "Computer Operation and Orientation of Seed Programme" has been organised with participation of 31 staff on May 21 -23, 2013 at IFFDC Head Office, Gurgaon

3. A One-day workshop on "Review of Computer Software E-Pawan of Seed Programme" has been organised with participation of 16 staff on May 24, 2013 at IFFDC Head Office, Gurgaon

4. A Two-days Training on "Advances in Seed Production, Processing & Safe Storage" with the participation of 24 staff member from Haryana, Punjab, Rajasthan, U.P. and Madhya Pradesh States was organized at Indian Agricultural Research Institute, Regional Station, Karnal during 31 May -June 01, 2013.

5. A Two-days Training on "Seed Production Technologies of Soybean" with the participation of 10 staff member Madhya Pradesh and Rajasthan States was organized at Directorate of Soybean Research, Indore during June 18-19, 2013.

6. A Two-days training on "Purchase procedure, powers of officers, accounting procedure, Auditing and other related aspects" has been organised with participation of 42 staff on July 10-11, 2013 at IFFCO-FMDI, Gurgaon

7. A Two-days training on "Work Ethics" has been organised with participation of 37 staff on September 3-4, 2013 at Om Shanti, Retreat Center, Manesar of Brahamakumaries.

8. During 31st January to 1st February, 2014 two days training programme on "Seed Quality Control" was organised at Kota, Rajasthan in which 34 staff participated.

9. Two-days training on "Self-Help Group Management" has been organized by IFFDC HO with participation of 32 staff during February 03-04, 2014 at NCDC TOPIC Institute, Gurgaon (Haryana).

प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. ने कई महत्वपूर्ण अनुभव व सीख प्राप्त की जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र की अन्य संस्थाओं, भागीदारों व अन्य सहयोगियों के लिए लाभदायक हो सकती है। इन अनुभवों व सीखों का आदान-प्रदान करने तथा प्रभाव व जुड़ाव का एक दायरा विकसित करने के लिए प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये गयें :-

- इफको की 40वीं वार्षिक आम सभा में श्री एन.पी. पटेल (अध्यक्ष, इफको) एवं डॉ. यू.एस. अवस्थी (प्रबंध निदेशक, इफको) ने आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रदर्शनी का भ्रमण किया तथा किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और देश की गरीब ग्रामीण समुदाय के लाभ हेतु इसका वृहद स्तर पर प्रसार करने के लिए उत्साहित किया। लगभग 600 प्रतिभागियों जिनमें इफको निदेशक, प्रतिनिधि तथा युवा प्रबन्धक शामिल थे, ने आई.एफ.एफ.डी.सी. प्रदर्शनी का भ्रमण किया।
- राष्ट्रीय दूरदर्शन चैनल के 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम में आई.एफ.एफ.डी.सी. गतिविधियों का तीन बार प्रसारण किया गया।
- भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 10-14 फरवरी, 2014 के दौरान नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित "कृषि बसंत-2014" में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी विभिन्न गतिविधियों की प्रदर्शनी लगायी। इस प्रदर्शनी का एक लाख से अधिक किसानों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों द्वारा अवलोकन किया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.) द्वारा 20-22 फरवरी, 2014 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित "कोआपरेटिव एक्सपो-2014" में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों की प्रदर्शनी लगायी गयी।
- राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी, द्वारा उ.प्र. बीज विकास निगम और कृषि विभाग के सहयोग से सितम्बर 12-14, 2013 के दौरान लखनऊ (उ.प्र.) में आयोजित राष्ट्रीय बीज कांग्रेस-2013 में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्रदर्शनी लगाकर अपनी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार किया।
- इफको द्वारा 18 सितम्बर, 2013 के दौरान ग्राम-भूना, जिला फतेहाबाद (हरियाणा) में आयोजित रबी फसल संगोष्ठी में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी गतिविधियों की प्रदर्शनी लगायी।
- उत्तर प्रदेश में नरेन्द्र देव कृषि विश्व विद्यालय, फैजाबाद द्वारा 9-10 अक्टूबर, 2013 को एवं चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा 25-27 फरवरी, 2014 के दौरान आयोजित किसान मेलों में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने हेतु भाग लिया।
- इफको फाउण्डेशन द्वारा 24 दिसम्बर, 2013 को हबीबुल्ला का बाग, जिला बाराबंकी (उ.प्र.) में तथा इफको द्वारा 22 फरवरी, 2014 को उन्नाव (उ.प्र.) में आयोजित कार्यक्रमों में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित किया।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराये।

PUBLICITY ACTIVITIES

In the process of implementing various interventions in its selected thematic areas, IFFDC has gained valuable experiences and lessons, which can be replicated by other partners and stakeholders. To share/ disseminate such experiences and learning, and also to develop a circle of influence and networking, the following steps have been taken under publicity component:

- During the 40th IFFCO Annual General Meeting, Shri N. P. Patel, Chairman, IFFCO and Dr. U. S. Awasthi, Managing Director, IFFCO visited the IFFDC exhibition stall and appreciated the efforts being made and encouraged their dissemination on a large scale for the benefit of the poor rural community of the country. About 600 participants including IFFCO Directors, Delegates and young managers visited IFFDC's stall.
- IFFDC activities were Broadcasted Three times on National television under Krishidarshan Programme.
- IFFDC placed an exhibition of its activities in the Krishi Basant 2014 (10 Feb-14 Feb 2014) organised by Ministry of Agriculture Govt. of India. More than one lakh farmers, Officers of State & Central Govt. and Scientists visited the stall.
- Exhibition on activities of IFFDC was displayed during Cooperative Expo-2014 (20-22 Feb 2014) at Pragati Maidan New Delhi Organised By National Cooperative Union of India (NCUI).
- An exhibition of IFFDC activities was displayed during September 12-14, 2013 in National Seed Congress-2013, Lucknow (U.P.) organized by NSRTC, Varanasi in joint collaboration with U.P. Beej Vikas Nigam and Department of Agriculture (U.P.)
- An exhibition of IFFDC activities was displayed during September 18, 2013 in IFFCO Rabi Crop Seminar organized at Village Bhuna, Fatehabad (Haryana).
- An exhibition of IFFDC activities was displayed in farmer fairs during October 9-10, 2013 at NDUAT, Faizabad (UP) and during February 25-27, 2014 at CSAU&T, Kanpur (UP).
- An exhibition of IFFDC activities has been laid during December 24, 2013 in IFFCO Foundation Programme organized at Habibullah-ka-Bagh, District Barabanki (UP) and during February 22, 2014 in IFFCO programme organized at Unnao (UP).
- IFFDC Published their Advetisement in various Magzines for publicity of organisation.

आभार

आपका निदेशक मंडल आलोच्य वर्ष के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर किये गये सतत् और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता है। कर्मचारियों के इन प्रयासों एवं कठिन परिश्रम के बिना समिति इन उत्साहजनक परिणामों एवं उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाती।

आपके निदेशक, इफको के निदेशक मंडल एवं प्रबन्धन विशेषतः डा. यू.एस. अवस्थी, प्रबन्ध निदेशक, इफको का अभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आई.एफ.एफ.डी.सी. को वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की। हम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; इफाड, लघु कृषक व्यापार संघ (एस. एफ.ए.सी.); ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी (रूडा) जयपुर; भारत-ओमान रिफाइनरी इंडिया लि., बीना, मध्य प्रदेश; भारत सरकार एवं राज्य सरकारों (राजस्थान और मध्य प्रदेश), के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनसे परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में निरन्तर आर्थिक सहयोग और अमूल्य मार्गदर्शन मिला। हम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त करते है जिन्होंने संस्था के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुऐ विभिन्न प्रदेशों मे भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुश्रवण का कार्य आई.एफ.एफ.डी.सी. को दिया।

निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी और उनकी टीम को उनके द्वारा समिति के विकास के प्रति समर्पित भाव के लिए हार्दिक बधाई देता है।

निदेशक मंडल, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों विशेषतः वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर; उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी तथा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान), नरेद्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर (उ.प्र.) तथा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा) के प्रति विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान किये गये सहयोग एवं तकनीकी सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु प्रदत्त सहयोग एवं आवश्यक सहायता के लिए आपका निदेशक मण्डल राज्य कृषि विभागों, भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं आदि का आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक, सदस्य समितियों के प्रति उनके द्वारा प्रदान किये गये निरन्तर सहयोग हेतु अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समिति के प्रबंधन में अपना विश्वास बनाए रखा।

निदेशक मंडल आश्वासन देना चाहता है कि आपकी समिति बहुमुखी प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करती रहेगी और आगामी वर्षों में नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(गुरू प्रसाद त्रिपाठी)
अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors wishes to place on record its deep appreciation for the dedicated efforts made by the employees of the Society at all levels during the year. Their unrelenting efforts and hard work have made such encouraging results and achievements by the Society possible.

Your Directors wish to acknowledge with gratitude the continued financial support and valuable guidance extended by IFFCO Board and Management, particularly by Dr. U. S. Awasthi, Managing Director, IFFCO, who has been the guiding and motivating spirit in the growth of IFFDC to high levels. We also thank National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, IFAD, Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC), RUDA, Jaipur, BORL. Government of India and State Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh for their support in the implementation of project activities. We also express gratitude to the Ministry of Rural Development (GoI) for reposing confidence in the organisation and assigning IFFDC the most prestigious task of monitoring centrally sponsored schemes and programmes being undertaken in various states.

The Board of Directors also wishes to express hearty congratulations to the Chief Executive and his team for their dedicated commitment to the betterment of society.

The Board of Directors also acknowledges with thanks the cooperation and technical support provided by various Research Institutes and Agriculture Universities, especially by Forest Research Institute (FRI), Dehradun; Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, National Research Centre for Agroforestry, Jhansi and National Research Center for Soyabean (NRCS), Indore, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (Rajasthan), Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj Faizabad (U.P.), Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (U.P.) and Ch. Charan Singh University of Agriculture, Hisar (Haryana).

The Board of Directors also expresses its sincere thanks to the various State Agriculture Departments, National Seed Association of India, National Seed Corporation, State Seed Corporation, State Seed Certification Agencies, etc for providing necessary support and help in the successful implementation of IFFDC's Seed Production Programme.

Your Directors also wish to express their deep gratitude to the Member Societies for their continued support and for reposing trust in the management of the Society.

The Board of Directors would like to assure you that your Society would continue to strive to achieve all-round progress and establish new records in the coming years.

For and On Behalf of the Board of Directors

(Guru Prasad Tripathi)
Chairman, IFFDC

पुरस्कार तथा सम्मान

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड को एक संस्था के रूप में निम्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है :

1. गरीब आदिवासी समुदाय की चिरन्तर आजीविका विकास के लिये उत्कृष्ट कार्य करने की दिशा में आजीविका विकास क्षेत्र में टाइम्स आफ इंडिया का सोशल इम्पैक्ट एवार्ड 2 अक्टूबर 2011 को माननीय डा. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में प्राप्त किया गया।

2. डॉ. एस. अय्यप्पन, सचिव (डी.ए.आर.ई.) एवं महानिदेशक आई.सी.ए.आर., डॉ. बंगाली बाबू राष्ट्रीय निदेशक एन.ए.आई.पी. नई दिल्ली एवं डॉ. ओ.पी. गिल कुलपति एम.पी.यु.ए.टी. उदयपुर द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी., उदयपुर को ग्रामीण गरीब समुदाय के लिए सुस्थिर आजीविका सुरक्षा में शोध के लिए किए गए विशेष योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

3. आई.एफ.एफ.डी.सी. को मनरेगा जलग्रहण परियोजना, श्योपुर में उत्तम कार्य के लिए जिलाधीश तथा एम.एल.ए. द्वारा 26 जनवरी, 2011 को सम्मानित किया गया।

4. आई.एफ.एफ.डी.सी. को झांकी प्रदर्शन के लिए श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, मंत्री, आदिवासी विकास, राजस्थान सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी, 2011 को प्रथम पुरस्कार प्रदत्त किया गया।

5. आई.एफ.एफ.डी.सी को "हरित राजस्थान कार्यक्रम" के अन्तर्गत उदयपुर संभाग में आदिवासी विकास मंत्री, श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय द्वारा 15 अगस्त, 2009 को उत्कृष्ट वानिकी कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

6. एमिटी इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल (एमिटी यूनीवर्सिटी), नोएडा, ने 5वीं ग्लोबल एच.आर. शिखरवार्ता के अवसर पर सफलता एवं विकास के लिए इसके सुसंगत एवं अथक प्रयासों से अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए **"एमिटी एच. आर. वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अवार्ड 2008"** प्रदत्त किया गया।

7. एमिटी इन्टरनेशनल बिजनेस स्कूल (एमिटी यूनीवर्सिटी), नोएडा, ने बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के विशिष्ट योगदान, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के प्रोत्साहन एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में योगदान के लिए **"एमिटी कारपोरेट एक्सीलेन्स अवार्ड 2008"** प्रदत्त किया गया।

8. अध्यक्ष आई.एफ.एफ.डी.सी. को अर्थ मैटर फाउंडशन, नई दिल्ली द्वारा देश में वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि का विकास करने हेतु **"अर्थ मैटर"** अवार्ड प्रदत्त किया गया।

9. **"उत्कृष्ट सामूहिक नागरिकता तथा स्थायित्व"** योग्य पहलों हेतु किये गये प्रयासों के लिए टेरी (द एनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट) द्वारा इसके सामूहिक सामाजिक दायित्व पुरस्कार 2004-05, 2007 तथा 2008 के अन्तर्गत तीन बार प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया है।

10. देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिये भारतीय व्यापार मंडल, मुंबई द्वारा **"पर्यावरण, कृषि तथा ग्रामीण विकास पुरस्कार 2002"** शीर्षित आई.एम.सी. डायमण्ड जुबली एण्डोवमेण्ट ट्रस्ट अवार्ड प्रदत्त किया गया।

11. वृक्षारोपण तथा बंजरभूमि विकास में विशिष्ट कार्य करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार, 1999"**। संस्था द्वारा संवर्द्धित पाँच प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (राजस्थान में सांगवा व रख्यावल, उत्तर प्रदेश में कटारी व मड़वा तथा मध्य प्रदेश में करैया) को विभिन्न वर्षों में बंजर भूमि विकास व वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

AWARDS AND RECOGNITION

The IFFDC has been honoured with several prestigious awards:

1. The Times of India "Social Impact Award" under the Livelihood category on 2nd October, 2011 in the presence of Hon'ble Dr.Manmohan Singh, Prime Minister of India, for its remarkable and excellent work on sustainable Livelihood Enhancement of the poor tribal community.

2. IFFDC Udaipur has been honoured with "Certificate of Appreciation" by Dr S. Ayyappan, Secretary (DARE) & Director General of ICAR, Dr BangaliBabu, National Director, NAIP, New Delhi and Dr O. P. Gill, Vice Chancellor of MPUAT, Udaipur for outstanding contribution of IFFDC in Research on Sustainable Livelihood Security of the poor rural community.

3. Excellent work in MGNREGA Watershed, Sheopur by District Collector & M.L.A., Sheopur (Madhya Pradesh) on 26th January, 2011.

4. First Prize for Tableau during Independence Day Celebration at Udaipur (Rajasthan) by Sh. Mahendrajit Singh Malviya, Minister, Tribal Development, Government of Rajasthan on 26th January 2011.

5. Excellent work of Plantation under "Harit Rajasthan Program" in Udaipur Division by Sh. Mahendrajit Singh Malviya, Minister, Tribal Development, Government of Rajasthan on 15th August 2009.

6. **"Amity HR Workplace Environment Award 2008"** conferred by Amity International Business School (Amity University), Noida on the occasion of 5th Global HR summit for its consistent and inexorable efforts to create a conducive environment yielding success and growth.

7. **"Amity Corporate Excellence Award 2008"** conferred by Amity International Business School (Amity University), Noida for IFFDC's outstanding contribution for afforestation on wasteland, environment conservation and promoting the growth of rural economy.

8. **"Earth Matter Award"** conferred on Chairman, IFFDC by Earth Matters Foundation, New Delhi for Integrated Development of Wastelands through afforestation in the country.

9. The **"Certificate of Appreciation"** of **"Corporate Social Responsibility"** Award 2004-05, 2007 and 2008 conferred by The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi for efforts made by the IFFDC towards initiatives for Corporate Citizenship and Sustainability.

10. IMC Diamond Jubilee Endowment Trust Award, titled **"Environment, Agriculture and Rural Development Award 2002"** conferred by Indian Merchants' Chamber, Mumbai for outstanding contribution to the cause of promoting the growth of rural economy in the country.

11. **"Indira Priyadarshini Vrikashamitra Puraskar 1999"** conferred by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India for excellence in afforestation and wasteland development. Five of its promoted PFFCS (Sangwa & Rakhyawal in Rajasthan, Katari & Madwa in Uttar Pradesh and Karaiya in Madhya Pradesh) have also been honoured with this award for their outstanding work in afforestation & wasteland development.

सहयोगी संस्थायें

1. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)
2. इंडिया कनाडा इनवायरनमेंट फैसिलिटी (आई.सी.ई.एफ.), कनाडा
3. डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.), यूनाइटेड किंगडम
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, भारत सरकार
5. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली
7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.), नई दिल्ली
8. राज्य सरकारें
9. रैन-फॉरेस्ट एलाइन्स, न्यूयार्क
10. राजस्थान राज्य सरकार के माध्यम से इन्टरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट (इफाड)
11. इंडीकस एनालाइटिक्स प्रा. लि., नई दिल्ली
12. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.), नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.), नई दिल्ली
14. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), नई दिल्ली
15. कोआपरेटिव रूरल डवलपमेन्ट ट्रस्ट (कोरडेट), फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
16. उत्तराखण्ड ग्राम विकास समिति, देहरादून, उत्तराखण्ड
17. राजस्थान मिशन ऑन स्किल एंड लाइवीहुड्स, जयपुर (राजस्थान)
18. भारतीय राज्य फार्म निगम (एस.एफ.सी.आई.)
19. भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, नई दिल्ली
20. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.), नई दिल्ली
21. इफको किसान संचार लिमिटेड (आई.के.एस.एल.), नई दिल्ली
22. इमरजेंट वेंचर ऑफ इण्डिया, गुडगांव, हरियाणा
23. इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलाईंस (आई.सी.ए.), एशिया पैसिफिक, नई दिल्ली
24. एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली
25. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.), नई दिल्ली
26. भारत-ओमान रिफाइनरी लि., बीना, मध्य प्रदेश
27. ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (रूडा), जयपुर, राजस्थान

SUPPORT ORGANISATION

1. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO).
2. India Canada Environment Facility (ICEF), Canada.
3. Department for International Development (DFID), United Kingdom (UK).
4. Ministry of Rural Development and Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt of India.
5. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
6. National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi.
7. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.
8. State Governments
9. Rain-forest Alliance, New York.
10. International Fund for Agriculture Development (IFAD) through State Government of Rajasthan.
11. Indicus Analytics Pvt. Ltd., New Delhi.
12. Ministry of Non-conventional Energy Sources (MNES), New Delhi.
13. National Afforestation and Eco Development Board (NAEB), New Delhi.
14. National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi
15. Cooperative Rural Development Trust (CORDET), Phulpur, Allahabad (UP).
16. Uttarakhand Gram Vikas Samiti, Dehradun (Uttarakhand).
17. Rajasthan Mission on Skill and Livelihoods (RMoL), Jaipur (Rajasthan).
18. State Farms Corporation of India (SFCI), New Delhi.
19. National Seed Association of India (NSAI), New Delhi.
20. National Seed Corporation Ltd. (NSC), New Delhi.
21. IFFCO Kisan Sanchar Ltd (IKSL), New Delhi.
22. Emergent Venture of India, Gurgaon, Haryana.
23. International Cooperative Alliance (ICA), Asia Pacific, New Delhi.
24. HDFC Bank, New Delhi.
25. Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC), New Delhi.
26. Bharat-Oman Refinery India Limited, Bina, Madhya Pradesh.
27. Rural Non-Farm Development Agency, Jaipur, Rajasthan.

अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय

1. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून, उत्तराखण्ड
2. उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर. आई.), जबलपुर, मध्य प्रदेश
3. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर, राजस्थान
4. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर, राजस्थान
5. अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट), हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
6. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, (एन.आर.सी.एस.), इंदौर, मध्य प्रदेश
7. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र (एन.आर.सी.ए.एफ.), झांसी, उत्तर प्रदेश
8. महाराणा प्रताप कृषि एवम् प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर, राजस्थान
9. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केन्द्र (आई.सी.आर.ए.एफ.), नई दिल्ली
10. सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान
11. गेंहूँ अनुसंधान निदेशालय, करनाल, हरियाणा

Research Institutes/Universities

1. Forest Research Institute (FRI), Dehradun, Uttarakhand
2. Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, Madhya Pradesh
3. Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Rajasthan
4. Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur, Rajasthan
5. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Hyderabad (AP)
6. National Research Center for Soyabean, (NRCS), Indore (Madhya Pradesh)
7. National Research Center for Agro-Forestry, (NRCAF), Jhansi (Uttar Pradesh)
8. Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur (Rajasthan)
9. International Centre for Research on Agriculture and Forestry. (ICRAF), New Delhi
10. Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur (Rajasthan)
11. Directorate of Wheat Research, Karnal (Haryana)